अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वैश्विक आर्थिक गतिविधियाँ भू-राजनीतिक अनिश्चितता में वृद्धि के बावजूद बनी रहीं। घरेलू अर्थव्यवस्था आघातसहनीय बनी रही, सूचीबद्ध निजी कंपनियों के तिमाही परिणामों ने कुल बिक्री वृद्धि में मजबूती दिखाई। औद्योगिक गतिविधियाँ मजबूत रहीं, और सेवा क्षेत्र ने अपने सुदृढ़ विकास को बनाए रखा। केंद्रीय बजट 2026-27 ने पूंजीगत व्यय की ओर आवंटन में वृद्धि करते हुए, दीर्घकालिक वृद्धि पर केंद्रित दृष्टिकोण को शिथिल किए बिना राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया। संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला के तहत पहले प्रिंट के अनुसार प्रमुख मुद्रास्फीति अभी भी कम बनी हुई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और भारतीय रुपए की स्थिति में पुनः सुधार हुआ, क्योंकि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते और अंतरिम भारत-यूएस व्यापार समझौते के बाद निवेशकों की धारणा में बदलाव आया।

परिचय

वैश्विक अनिश्चितता सितंबर 2025 में अपने चरम स्तर से धीरे-धीरे घटती रही, यद्यपि यह सामान्य स्तर से ऊपर बनी रही। हालांकि, जनवरी में भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी, जिसने वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता में योगदान दिया।

मुश्किल हालात के बावजूद, वैश्विक आर्थिक गतिविधियाँ आघातसहनीय बनी रहीं, और उच्च आवृत्ति संकेतक जनवरी में कुछ सुधार का संकेत दे रहे हैं। हालांकि, विस्तार की गति प्रभावित रही और अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी आशावाद का स्तर कम रहा। नए निर्यात आदेश कमजोर बाहरी मांग के बीच लगातार संकुचित होते रहे, और निर्माण एवं सेवाओं के निर्यात में व्यापक रूप से गिरावट देखी गई।

वैश्विक इक्विटी बाजारों ने जनवरी और फरवरी की शुरुआत में तेजी दिखाई, जो अपेक्षाओं से मजबूत आर्थिक डेटा और 2024 की चौथी तिमाही के लाभ परिणामों से लाभान्वित हुए, लेकिन इसके बाद तकनीकी क्षेत्र में बिक्री के कारण सुधार आया। उभरते बाजारों ने अमेरिका से पोर्टफोलियो विविधीकरण और एशिया के सेमीकंडक्टर निर्माताओं की ओर एआई-संबंधित निवेशों के पुनर्वितरण के बीच बेहतर प्रदर्शन किया। बॉन्ड बाजार उच्च सरकारी उधारी और केंद्रीय बैंक की बॉन्ड होल्डिंग्स की निरंतर मुक्त करने के दबाव के तहत सुस्त रहे। उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया - जनवरी के महीने के लिए यह अब तक का सबसे उच्च स्तर है - जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों सेगमेंट में मजबूत अंतर्वाह रहा। वैश्विक एफ़डीआई प्रवाह 2025 में बढ़े, जिसमें डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर में निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्वाह प्रमुख थे, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाह सीमित रहे।

वैश्विक जिंस कीमतों ने जनवरी और फरवरी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रवृत्तियाँ दर्ज कीं। विश्व बैंक जिंस मूल्य सूचकांक जनवरी में 10 महीने के उच्च स्तर तक पहुँच गया, जो धातु और ऊर्जा मूल्यों में तेजी के कारण था। रिकॉर्ड उच्च स्तर से, सोना और चाँदी के मूल्य जनवरी के अंत तक राजनीतिक तनावों में कमी और संशोधित मार्जिन आवश्यकताओं के कारण नकदी जुटाने के लिए सोने की बिक्री (चलनिधिकरण) होने पर अत्यधिक गिरावट दिखाई। कच्चे तेल की कीमतें अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव के चलते आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों की चिंताओं के कारण मजबूत हुई।

जनवरी में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति में मध्यमता आई, जबकि प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में भिन्न-भिन्न रुझान देखे गए। अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने जनवरी-फरवरी में मुद्रास्फीति पर जारी उच्च जोखिम और लंबित भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मौजूदा स्थिति को बनाए रखा। केवल ऑस्ट्रेलिया ने ऊंची सेवा

* यह लेख रेखा मिश्रा, राजीब दास, आशीष थॉमस जॉर्ज, शशी कांत, रजनी दहिया, विस्वजीत मोहंती, ऊर्जा यादव, अमीन अशरफ, बजरंगी लाल गुप्ता, भाग्यश्री चट्टोपाध्याय, नीलव दास, हर्षिता यादव, ऐट्टम अभिग्नू यादव, प्रशांत कुमार, ऋषभ कुमार, सिद्धार्थ छापोलिया, सृतमा राय, शिवम, अर्चना दिलीप, मनीष कुमार त्रिपाठी, स्निग्धा योगिंद्रन, श्रेया गुप्ता, मोनिका, समृद्धि, कमल गुप्ता, पलक गोयल और सौरभ शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। उपगवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। थंगजासोन सोना, पवन गोपालकृष्णन और धन्या वी द्वारा किए गए सहकर्मी समीक्षा के लिए भी आभार व्यक्त किया जाता है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

लागत और कड़े श्रम बाजार के बीच अपनी नीतिगत दर बढ़ाई, जबकि रूस ने घरेलू विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी दर कम की।

जनवरी में घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ मजबूत बनी रहीं, जो मजबूत मांग की परिस्थितियों द्वारा संचालित थीं। सूचीबद्ध निजी कंपनियों के त्रैमासिक परिणाम कुल बिक्री वृद्धि में मजबूती दिखाते हैं। रबी की बुवाई सभी प्रमुख फसलों में अधिक क्षेत्रफल के साथ पूरी हुई। औद्योगिक गतिविधियाँ मजबूत रहीं, और सेवा क्षेत्र ने अपनी स्वस्थ वृद्धि बनाए रखी।

केंद्रीय बजट 2026–27 ने विकास की आवश्यकताओं को राजकोषीय विवेक के साथ संतुलित किया। राजकोषीय सुधार के विश्वसनीय मार्ग का पालन करते हुए, पूंजीगत व्यय पर मजबूत जोर बनाए रखते हुए, और अवसंरचना, नवाचार और मानव पूंजी विकास को प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने दीर्घकालिक विकास की नींव को मजबूत किया। राजस्व व्यय को सीमित रखना और विकास-प्रेरक निवेश पर निरंतर ध्यान देना गुणवत्ता वाले खर्च के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 12 फरवरी, 2026 को जनवरी 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जारी की, जिसमें आधार वर्ष को अपडेट करते हुए (2024=100) पेश किया गया। संशोधित श्रृंखला के तहत पहली मुद्रास्फीति रिपोर्ट में, जनवरी में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति 2.8 प्रतिशत रही, जबकि खाद्य और मूल मुद्रास्फीति क्रमशः 2.1 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत रही। कीमती धातुओं को बाहर करने के बाद, मूल मुद्रास्फीति 1.9 प्रतिशत के निम्न स्तर तक गिर गई।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी 2026 की अपनी द्विमासिक समीक्षा में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने तटस्थ रुख जारी रखने का भी फैसला किया। ये निर्णय विकास की गति के आघातसहनीय और मुद्रास्फीति के लिए एक सौम्य दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित थे।

जनवरी के दूसरे पखवाड़े के दौरान वित्तीय स्थितियों में मध्यम कठोरता देखी गई। जनवरी में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स (सीपी) और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) पर ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, फरवरी में सरकारी खर्च में तेजी लाने और आरबीआई के चलनिधि उपायों के माध्यम से पर्याप्त नकदी बहाल की गई थी। चलनिधि की स्थिति को दर्शाते हुए, भारित औसत कॉल दर फरवरी में पॉलिसी रेपो दर से ऊपर से नीचे हो गई। जमा और ऋण में वृद्धि मजबूत बनी हुई है और ऋण में वृद्धि जमा की तुलना में अधिक है। 2025-26 (31 जनवरी, 2026 तक) के दौरान, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह बैंक और गैर-बैंक दोनों स्रोतों से ऋण द्वारा समर्थित रहा।

टैरिफ अनिश्चितताओं और नए सिरे से भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच जनवरी 2026 में भारतीय इक्विटी मार्केट कम रहा. महीने के अंत में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के माध्यम से इसे बढ़ावा मिला। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की वापसी से फरवरी की शुरुआत में इसमें तेजी आई। रुपये में भी उछाल आया क्योंकि निवल एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया.

इस संदर्भ में, शेष लेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदल रही परिस्थितियों को कवर करता है। खंड III घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रदान करता है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को समाहित करता है, जबकि खंड V समापन टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

II. वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक अनिश्चितता, हालांकि अभी बढ़ी हुई है, जनवरी में लगातार चौथे महीने इसमें गिरावट आई, साथ ही नीतिगत अनिश्चितता में नरमी भी आई। हालांकि, वेनेजुएला, मध्य पूर्व, रूस-यूक्रेन संघर्ष और ग्रीनलैंड पर विवाद में बढ़ते तनाव के बीच भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक में वृद्धि हुई। वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता में बढ़ोतरी के लिए सॉफ्टवेयर उद्योग में एआई से संबंधित व्यवधानों के बारे में चिंताओं के साथ-साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव भी एक प्रमुख कारक थे (चार्ट II.1ए और II.1बी)।

चार्ट II.1: वैश्विक अनिश्चितता कम हुई, बाजार अस्थिरता बढ़ी

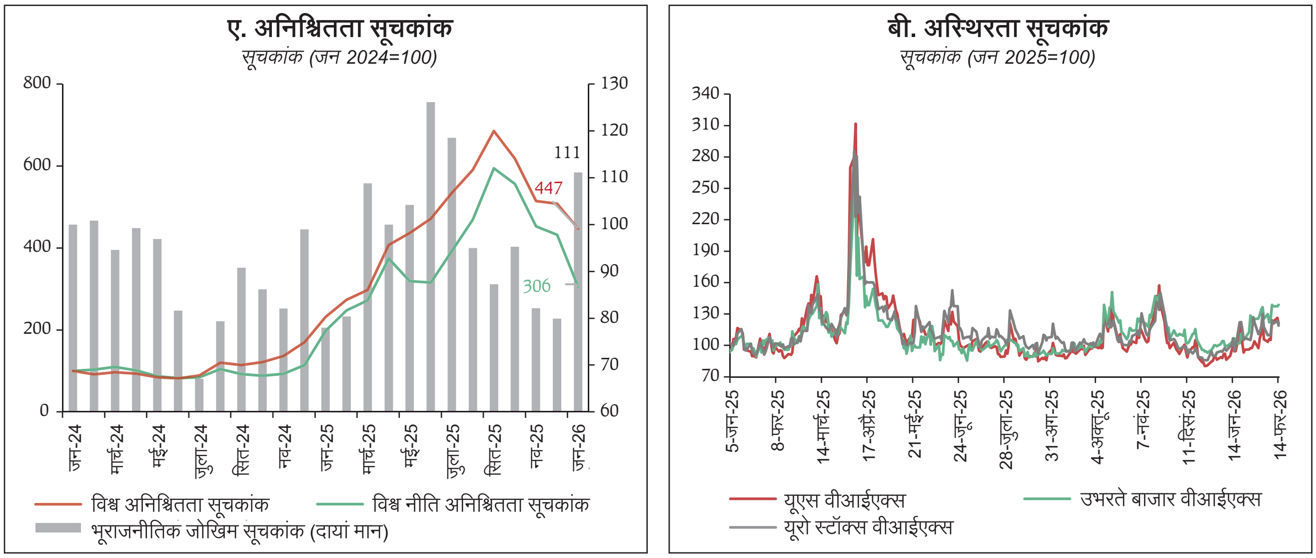

स्रोत: शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज: डारियो काल्डारा और माटेओ लैकोविएलो; ब्लूमबर्ग; और विश्व अनिश्चितता सूचकांक (डबल्यूयूआई) डेटाबेस।

वैश्विक सम्मिलित पीएमआई जनवरी में पिछले महीने के छह महीने के निचले स्तर से बेहतर हुआ। हालांकि, नए निर्यात आदेश संकुचन में बने रहे, जो विनिर्माण और सेवाओं दोनों में निर्यात आदेशों में व्यापक आधार वाली गिरावट से प्रेरित रहे (सारणी II.1)।

जैसा कि पीएमआई सूचकों में परिलक्षित होता है, मुख्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में व्यापार गतिविधियाँ बढ़ी, सिवाय फ्रांस और कनाडा के। मुख्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, व्यापार गतिविधियों के विस्तार का भारत द्वारा नेतृत्व किया गया, जबकि चीन और रूस में यह अपेक्षाकृत मामूली दर से बढ़ी। मुख्य एई में, नई निर्यात आदेशों में संकुचन बना रहा, केवल यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। मुख्य ईएमडीई में, निर्यात आदेश भारत और चीन में बढ़े, जबकि रूस में यह अपरिवर्तित रहे (चार्ट II.2ए और II.2बी)।

जनवरी में वैश्विक जिंस मूल्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विरोधाभासी मूल्य उतार चढ़ाव देखा गया। विश्व बैंक का जिंस मूल्य सूचकांक

सारणी II.1: वैश्विक संयोजित पीएमआई में सुधार, निर्यात आदेशों में संकुचन बना रहा

	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26
पीएमआई संयोजित	51.8	51.5	52.1	50.8	51.2	51.7	52.5	52.9	52.5	53.0	52.7	52.0	52.5
पीएमआई विनिर्माण	50.1	50.6	50.3	49.8	49.5	50.4	49.7	50.9	50.7	50.9	50.5	50.4	50.9
पीएमआई सेवाएँ	52.2	51.5	52.7	50.8	52	51.8	53.5	53.3	52.9	53.5	53.2	52.4	52.7
पीएमआई निर्यात आदेश	49.6	49.7	50.1	47.5	48.0	49.1	48.5	48.9	49.7	48.6	50.0	49.2	49.7
पीएमआई निर्यात आदेश: विनिर्माण	49.4	49.6	50.1	47.3	48.0	49.2	48.2	48.7	49.5	48.3	49.9	49.1	49.9
पीएमआई निर्यात आदेश: सेवाएँ	50.2	50.2	50.1	48.2	47.9	48.7	49.4	49.3	50.2	49.4	50.2	49.6	49.0

50

<<<<<< संकुचन------------------ विस्तार >>>>>>

टिप्पणीयाँ: 1. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), एक प्रसार सूचकांक, प्रत्येक चर में पिछले महीने की तुलना में परिवर्तन को पकड़ता है, यह नोट करते हुए कि प्रत्येक में वृद्धि/सुधार हुआ है, गिरावट/खराबी हुई है या कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीएमआई मान >50 का अर्थ है विस्तार; <50 का अर्थ है संकुचन; और = का अर्थ है 'कोई बदलाव नहीं'।

2. हीट मैप अप्रैल 2023 से डेटा पर लागू किया गया है। मानचित्र रंग कोडित है - लाल का अर्थ न्यूनतम मान है, पीला का अर्थ 50 (या परिवर्तन मान) है, और हरा का अर्थ है प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में उच्चतम मान।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल.

चार्ट II.2: क्रय प्रबंधक सूचकांक: विभिन्न क्षेत्राधिकारों में तुलना

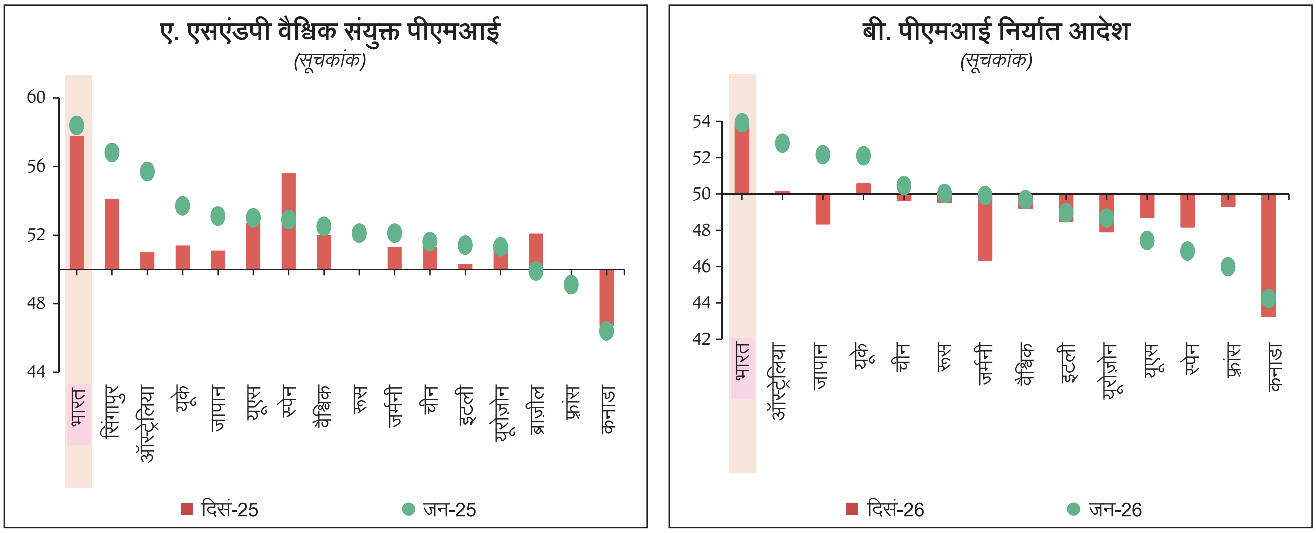

टिप्पणी: 50 का स्तर दर्शाता है कि गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं है, 50 से अधिक का मान विस्तार दर्शाता है और 50 से कम संकुचन की ओर संकेत करता है।
स्रोत: एस&पी ग्लोबल

जनवरी में धातु और ऊर्जा मूल्यों में तेज वृद्धि के कारण 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके विपरीत, खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक जनवरी में पांचवें लगातार महीने गिरा, जिसमें मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों, मांस और चीनी के मूल्यों में कमी का प्रभाव रहा (चार्ट II.3ए)। ब्लूमबर्ग जिंस सूचकांक, जनवरी के मध्य में तेज वृद्धि दर्शाने के बाद, फरवरी तक सुधार की ओर लौटा, जो मुख्यतः सोने और चांदी के मूल्यों में हुए भारी उतार-चढ़ाव से प्रेरित था। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से जनवरी में सोने के मूल्यों में तेज उछाल आया; हालांकि, महीने के अंत और फरवरी की शुरुआत में तनावों में कमी, लाभ वसूली और उच्च मार्जिन आवश्यकताओं के कारण इसमें सुधार आया। तत्पश्चात, जोखिम से बचाव की नई

चार्ट II.3: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें

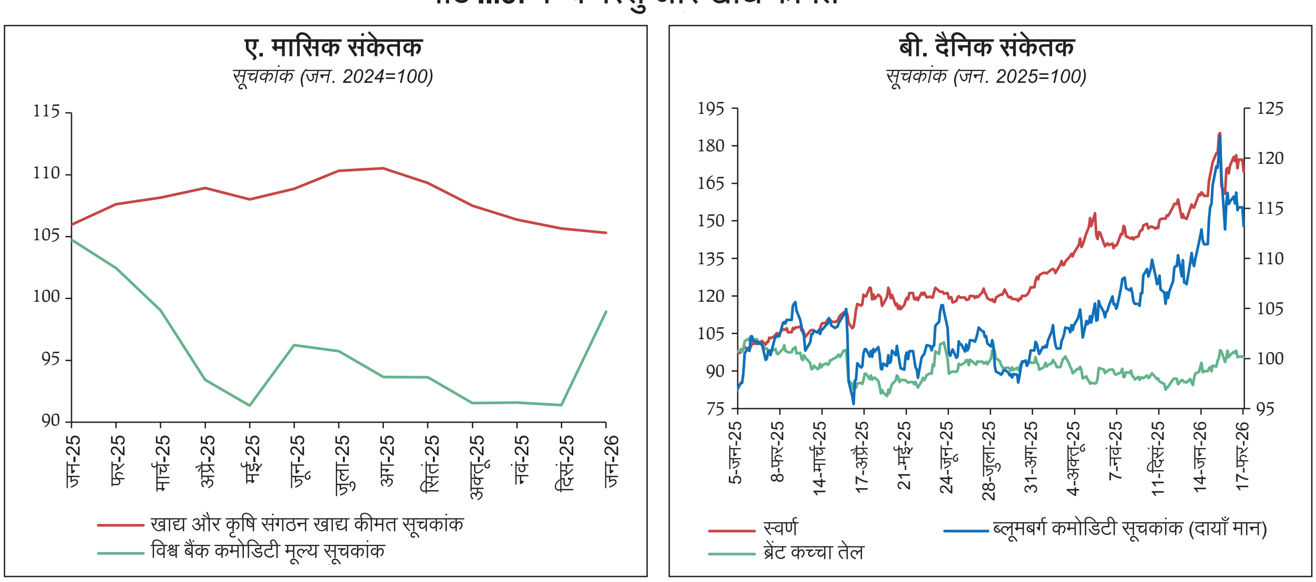

स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन; ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट।

लहर के कारण मूल्यों ने कुछ मजबूती हासिल की। कच्चे तेल के मूल्यों में भी जनवरी और फरवरी की शुरुआत में बढ़े हुए भू-राजनीतिक दबावों के कारण तेजी आई (चार्ट II.3बी)।

जनवरी में प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में मंदी आई, जबकि प्रमुख उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह विभिन्न दिशाओं में गतिशील रही। यूरो क्षेत्र में, कम ऊर्जा लागत के कारण समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट आई। अमेरिका में, आवास और ऊर्जा कीमतों में नरमी के बीच मुद्रास्फीति में कमी आई, तथा मूल मुद्रास्फीति घटकर पांच वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 में, जापान में मुद्रास्फीति में बिजली और ऊर्जा कीमतों में गिरावट के कारण तेज कमी दर्ज की गई, जबकि यूके में उच्च सेवा और खाद्य कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई (चार्ट II.4ए)। प्रमुख उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, चीन में मुद्रास्फीति तीन लगातार महीनों की वृद्धि के बाद मंद पड़ी और मुख्य रूप से कम खाद्य कीमतों के कारण अपस्फीति क्षेत्र के निकट पहुंच गई। पिछले तीन महीनों में स्थिर रहने के बाद चीन में मूल मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। रूस में, सरकार द्वारा मूल्य वर्धित कर में वृद्धि किए जाने के बाद, नौ महीने की गिरावट के पुनः मुद्रास्फीति में तेजी आई (चार्ट II.4बी)।

वैश्विक इक्विटी बाजारों में जनवरी-फरवरी के दौरान अपेक्षाओं से बेहतर आर्थिक गतिविधि के आंकड़ों और चौथी तिमाही (2025) के नतीजों के समर्थन से तेजी देखी गई, जिसके बाद प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिकवाली के चलते इनमें गिरावट आई। जापान में, फरवरी में हुए अचानक आम चुनावों में प्राप्त स्पष्ट जनादेश के बाद राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की संभावनाओं से भावनाओं को बल मिलने के कारण बाजारों में तेजी का सिलसिला जारी रहा। निवेशकों द्वारा अमेरिकी परिसंपत्तियों से हटकर अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण करने के मद्देनजर यूरोपीय इक्विटी सूचकांकों में वृद्धि हुई। लगातार जारी घरेलू नीतिगत अनिश्चितताओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिकवाली के बीच अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन अन्य बाजारों की तुलना में कमजोर रहा। चीनी स्टॉकों में, विनिर्माण गतिविधियों में कमजोरी और इंटरनेट कंपनियों पर करारोपण को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण बिकवाली का दबाव देखा गया (चार्ट II.5ए)।

वैश्विक इक्विटी बाजारों के प्रौद्योगिकी खंड के भीतर, प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) फर्मों और अन्य सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (एसएएएस) फर्मों के प्रदर्शन में विचलन देखा गया। फरवरी माह में, जेनरेटिव एआई-आधारित उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर, एसएंडपी 500 पारंपरिक सॉफ्टवेयर और सेवाएं सूचकांक में ब्लूमबर्ग मैग्निफिसेंट 7 सूचकांक की तुलना में तेज गिरावट दर्ज की गई (चार्ट II.6)।

चार्ट II.4: हेडलाइन मुद्रास्फीतिं

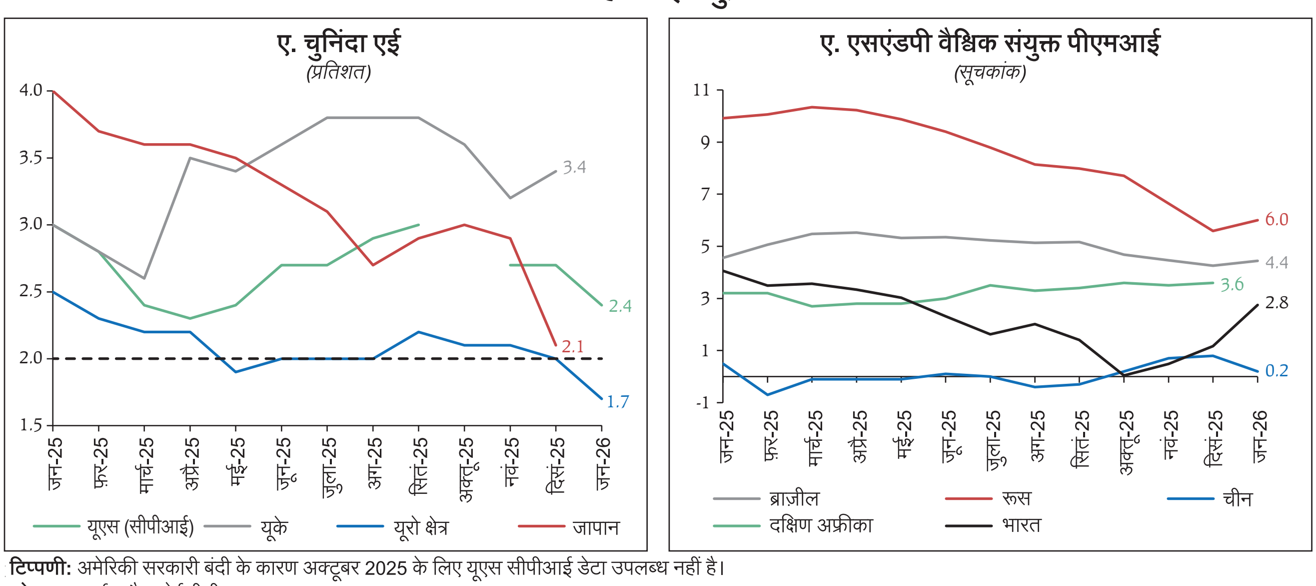

टिप्पणी: अमेरिकी सरकारी बंदी के कारण अक्टूबर 2025 के लिए यूएस सीपीआई डेटा उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग: और ओईसीडी।

चार्ट II.5 : वैश्विक वित्तीय बाज़ार

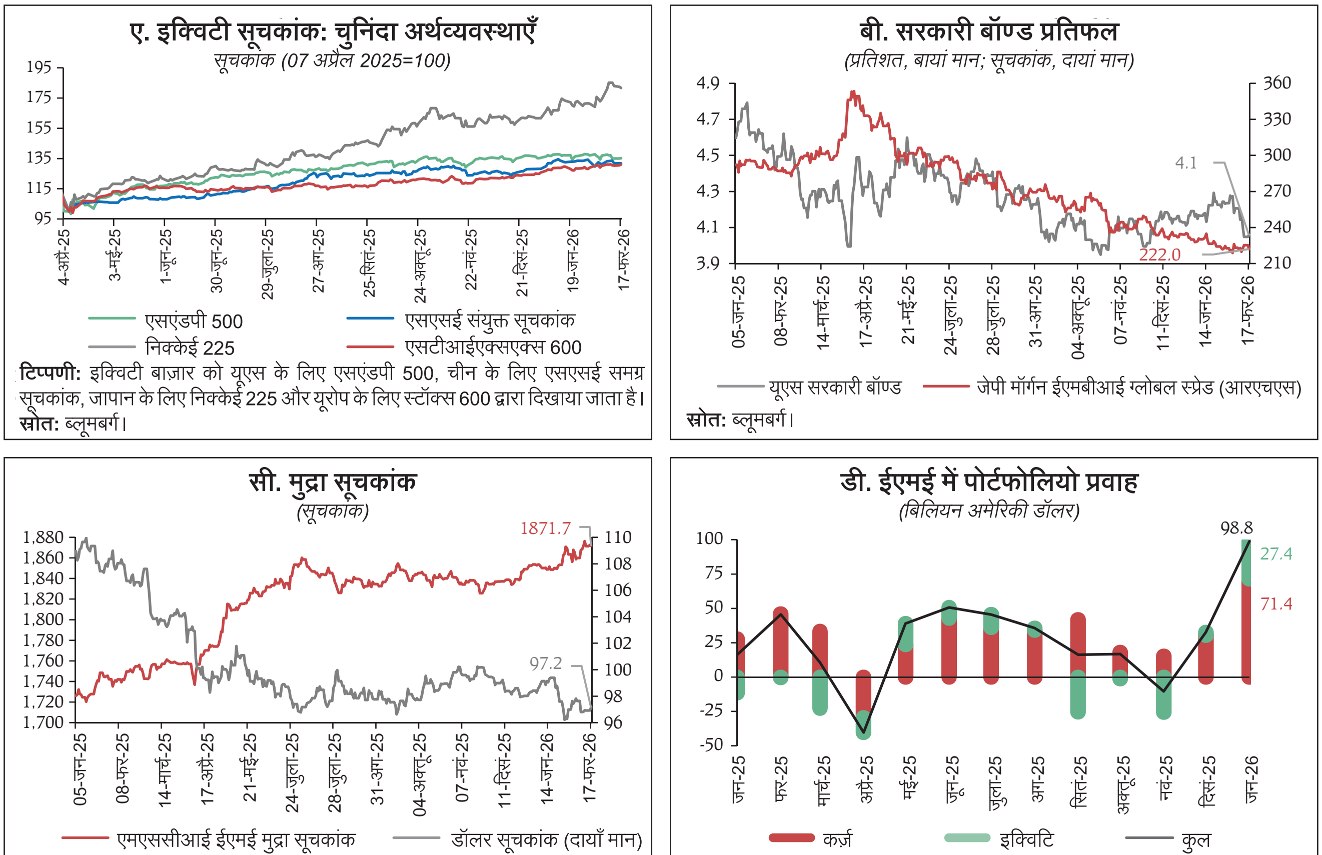

टिप्पणी: इक्विटी बाज़ार को यूएस के लिए एसएंडपी 500, चीन के लिए एसएसई समग्र सूचकांक, जापान के लिए निक्केई 225 और यूरोप के लिए स्टॉक्स 600 द्वारा दिखाया जाता है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

वैश्विक बॉंड सूचकांकों की गतिविधियां केंद्रीय बैंकों द्वारा बॉंड होल्डिंग्स को जारी रखने के साथ-साथ बढ़ते सार्वजनिक व्यय को लेकर बढ़ती चिंताओं से प्रभावित रहीं। अमेरिका में अपेक्षाओं से बेहतर रोजगार आंकड़ों के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर विराम लगा, जिससे जनवरी में अमेरिकी ट्रेजरी बॉंड प्रतिफल में वृद्धि हुई। हालांकि, फरवरी में इक्विटी बाजारों में बिकवाली के बाद सुरक्षित निवेश की मांग और जनवरी में मुद्रास्फीति के नरम आंकड़ों के चलते उपज में नरमी आई। जापान में भी जनवरी में राजकोषीय चिंताओं के कारण प्रतिफल वक्र में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के कमजोर आंकड़ों के बाद यह स्थिर रहा। जेपी मॉर्गन उभरते बाजार बॉंड प्रतिफल स्प्रेड में संकुचन देखा गया, जो उभरते बाजारों के लिए बेहतर आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है (चार्ट II.5बी)।

चार्ट II.6: जनरेटिव एआई फर्मों की तुलना में सॉफ़्टवेयर और सेवाओं के शेयरों में अधिक तेजी से गिरावट

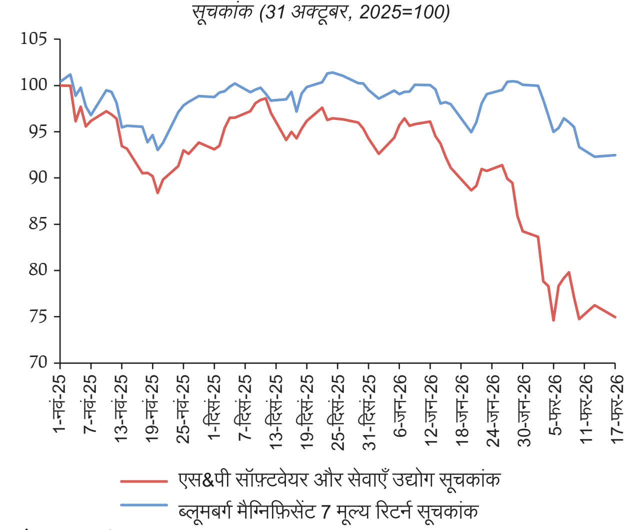

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

अमेरिकी डॉलर जनवरी के मध्य तक अपेक्षाकृत स्थिर रहा, इससे पहले एफओएमसी की बैठक से पूर्व निवेशकों की चिंताओं और मुद्रा के अवमूल्यन के भय के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि के कारण इस पर गंभीर अवमूल्यन का दबाव बना। नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन की घोषणा के बाद यह जनवरी के

अंत और फरवरी की शुरुआत में इसमें आंशिक रूप से सुधार हुआ (चार्ट II.5सी)। एशिया के लिए बेहतर आर्थिक परिदृश्य और निवेशकों द्वारा यूएस संपत्तियों से विविधीकरण के समर्थन से उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह पांच वर्ष के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया (चार्ट II.5डी)।

वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) प्रवाह में वर्ष 2025 में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसका नेतृत्व डेटा सेंटर्स और उन्नत चिप्स में बढ़े हुए निवेश ने किया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अवसंरचना और डिजिटल नेटवर्क के लिए बढ़ती मांग को दर्शाता है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, वहीं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाह में मंदी देखी गई (चार्ट II.7)।

चार्ट II.7: 2025 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई प्रवाह बढ़ा, विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं मेंसंयमित रहा

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

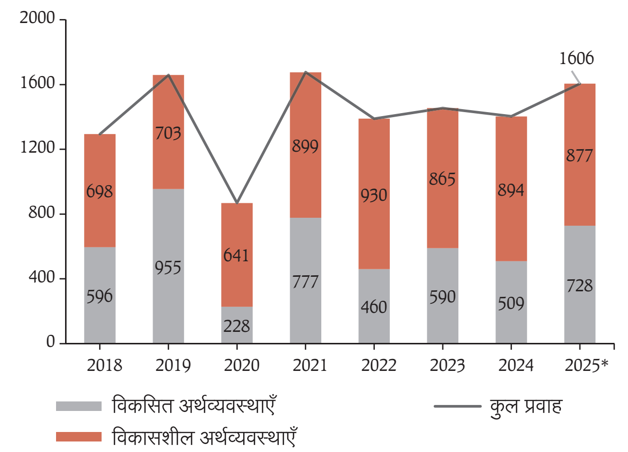

*: वर्ष 2025 के पूरे डेटा का अनुमान पहले तीन तिमाहियों के आधार पर लगाया गया है।

स्रोत: यूएनसीटीएडी

जनवरी में, अधिकांश प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति पर बने लगातार ऊपर की ओर के जोखिमों और भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर अमेरिका, जापान, कनाडा, स्वीडन और दक्षिण कोरिया ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने बेंचमार्क ब्याज दरों को स्थिर रखा। फरवरी माह में अब तक, यूके, यूरो क्षेत्र, मेक्सिको और न्यूजीलैंड ने अपनी दरों को अपरिवर्तित रखा है। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीतिगत दर में वृद्धि की, जबकि रूस ने इसे कम किया (चार्ट II.8)।

चार्ट II.8: अधिकांश प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों ने जनवरी में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया

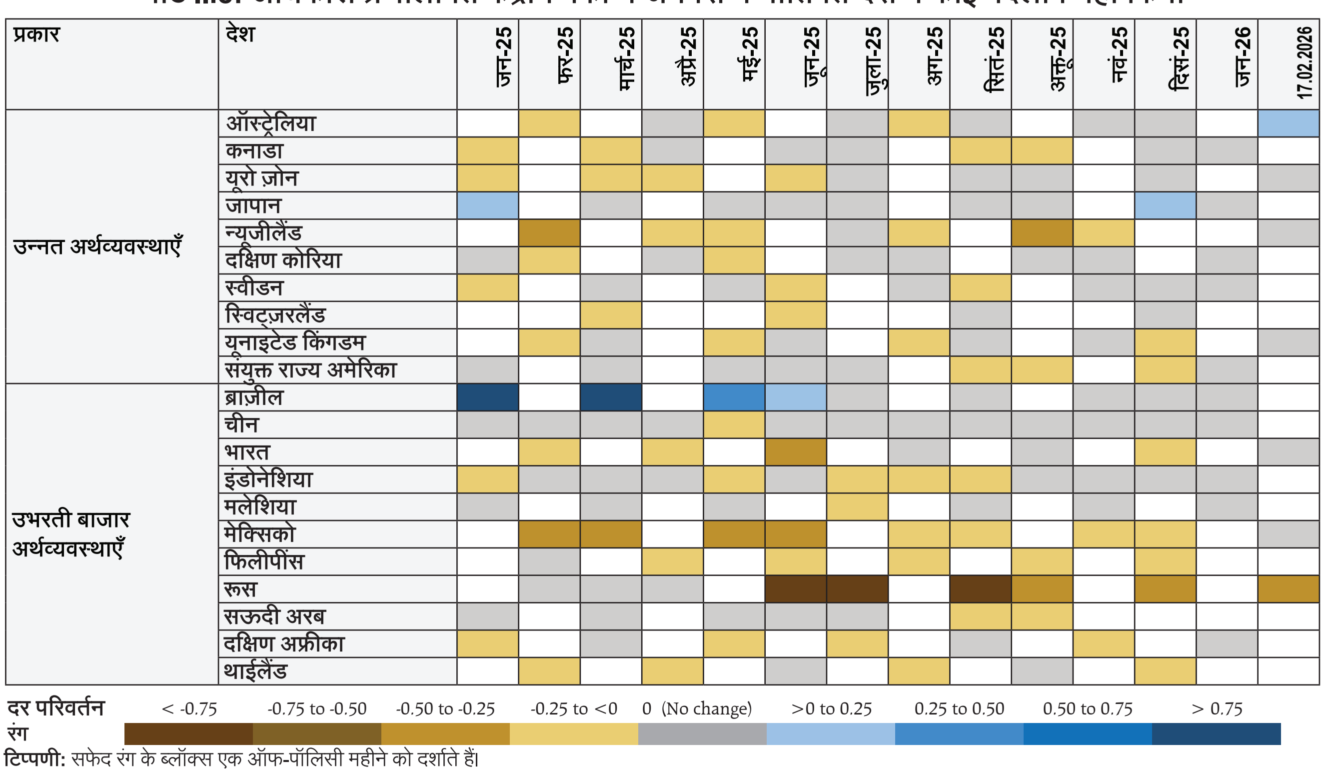

टिप्पणी: सफेद रंग के ब्लॉक्स एक ऑफ-पॉलिसी महीने को दर्शाते हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

III. घरेलू विकास

जनवरी में आर्थिक गतिविधियां तेज मांग की स्थितियों के सहारे आघातसहनीय बनी रहीं। सूचीबद्ध निजी कंपनियों के तिमाही परिणाम समग्र बिक्री वृद्धि में मजबूती को दर्शाते हैं। औद्योगिक गतिविधियां मजबूत बनी रहीं और सेवा क्षेत्र अपनी मजबूत वृद्धि को बनाए रखने में सफल रहा। केंद्रीय बजट 2026-27 ने पूंजीगत व्यय की ओर आवंटन में वृद्धि करते हुए, दीर्घकालिक वृद्धि पर केंद्रित दृष्टिकोण को शिथिल किए बिना राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के 16वें आयोग की अधिकांश सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत राज्यों द्वारा भारत की वृद्धि में किए गए योगदान को मान्यता देते हुए निधियों के क्षैतिज हस्तांतरण के लिए एक नए सूत्र को अपनाया गया है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी 2026 की अपनी द्विमासिक समीक्षा में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। एमपीसी ने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। ये निर्णय वृद्धि की गतिशीलता में आघातसहनीयता और मुद्रास्फीति के लिए अनुकूल परिदृश्य द्वारा संचालित थे।

समग्र मांग

जनवरी माह में ऊर्जा खपत, डिजिटल भुगतान, व्यापार और रसद से संबंधित उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियां आघातसहनीय बनी रहीं। जीएसटी दरों के युक्तिकरण के समर्थन से ई-वे बिलों में दो अंकीय वृद्धि दर्ज करना जारी रहा। बिजली की मांग में मजबूत वृद्धि बनी रही, जो मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में शीत लहर की स्थितियों के कारण बढ़ी मांग, साथ ही सतत औद्योगिक गतिविधियों के कारण थी। जीएसटी राजस्व में वृद्धि स्थिर रही। यद्यपि पेट्रोलियम खपत की वृद्धि दर में मंदी आई, फिर भी यह आघातसहनीय बनी रही। डिजिटल भुगतान में लेन-देन के मूल्य और मात्रा दोनों में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त 2025 में फास्टैग वार्षिक पास योजना के परिचय के बाद देखी गई गिरावट की प्रवृत्ति जनवरी में भी टोल संग्रहण में जारी रही (सारणी III.1)[1]।

सारणी III.1: कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर बनी रहीं

सकेतक	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिसं-25	जन-26
जीएसटी ई-वे बिल	23.1	14.7	20.2	23.4	18.9	19.3	25.8	22.4	21.0	8.2	27.6	23.5	15.8
जीएसटी राजस्व	12.3	9.1	9.9	12.6	16.4	6.2	7.5	6.5	9.1	4.6	3.6	6.1	6.2
टोल संग्रह	14.8	18.7	11.9	16.6	16.4	15.5	14.8	16.1	13.8	4.6	2.9	0.4	-1.8
विद्युत की मांग	1.3	2.4	5.7	2.8	-4.8	-2.3	2.6	3.8	3.5	-5.8	-0.6	6.5	4.5
पेट्रोलियम खपत	3.0	-5.2	-3.1	0.2	1.1	0.5	-4.4	4.8	7.0	-1.5	2.8	5.3	2.9
जिसमें पेट्रोल	6.7	5.0	5.7	5.0	9.2	6.8	5.9	5.5	8.0	7.4	2.6	7.1	5.6
डीज़ल	4.2	-1.3	0.9	4.2	2.1	1.5	2.4	1.2	6.5	-0.3	4.7	5.0	3.1
विमानन टरबाइन ईंधन	9.4	4.2	5.7	3.9	4.4	3.3	-2.3	-2.9	-0.8	2.1	5.4	0.3	4.7
डिजिटल भुगतान – मात्रा	33.0	26.7	30.8	30.0	29.2	28.3	30.9	31.1	28.1	21.5	30.2	26.8	22.3
डिजिटल भुगतान – मूल्य	18.6	9.5	17.3	18.4	12.6	17.4	16.6	5.3	13.4	8.8	14.7	15.2	11.5

<<संकुचन --- विस्तार>>

टिप्पणी: 1. सभी संकेतकों की व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।

2. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। दिसंबर 2025 के लिए डिजिटल भुगतान डेटा अनंतिम है।

3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग उस डेटा सीरीज़ की सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।

4. जनवरी 2026 के लिए टोल संग्रह की वृद्धि दर के डेटा की गणना प्रतिदिन के डेटा को मिलाकर की जाती है।

स्रोत: वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); आरबीआई, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए); भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

[1] वार्षिक पास ने उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित शुल्क पर वर्ष भर में अधिकतम 200 यात्राएँ करने या यात्रा करने की अनुमति दी, जिससे प्लाज़ाओं में प्रति यात्रा टोल राजस्व में कमी आई।

जनवरी माह में समग्र मांग की स्थितियां उत्साहवर्धक बनी रहीं। जीएसटी के बाद मिले वेग और खरीफ फसल तथा विवाह सीजन से प्राप्त स्वस्थ ग्रामीण नकदी प्रवाह के समर्थन से, दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री में वृद्धि दर तेज होने के साथ ग्रामीण मांग और भी मजबूत हुई। जनवरी में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में विस्तार जारी रहा, हालांकि यह गति धीमी थी। बिक्री में आई यह गिरावट जीएसटी दरों के युक्तिकरण द्वारा प्रेरित उच्च मांग की अवधि के बाद बाजारों के सामान्यीकरण को दर्शाती है। उड़ान समय सारणी में व्यवधान के कारण दिसंबर में आई गिरावट के बाद, घरेलू हवाई यात्री यातायात में सुधार हुआ (सारणी III.2)।

वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में समग्र भारत की बेरोजगारी दर, जो दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत थी, घटकर 4.8 प्रतिशत हो गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों[2] में कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त, श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में मामूली गिरावट आई। हालांकि, जनवरी में दिसंबर की तुलना में समग्र भारत की बेरोजगारी दर में मामूली वृद्धि हुई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों दरों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में मामूली गिरावट आई, जो शीत ऋतु की स्थितियों और फसल कटाई के बाद की ढील[3] जैसे मौसमी कारकों को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए पीएमआई रोजगार में जनवरी में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए पीएमआई रोजगार विस्तार के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक ने बीपीओ/आईटीईएस, आतिथ्य और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में स्थिर भर्ती के बावजूद नई भर्तियों में मंदी दिखाई। इस बीच, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग लगातार सातवें महीने भी घटती रही, जो ग्रामीण श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार को दर्शाती है (सारणी III.3)।

अप्रैल-दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमानों (आरई) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के सभी प्रमुख घाटा संकेतक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम रहे (चार्ट III.1ए)[4]। राजकोषीय घाटे में यह कमी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि और राजस्व व्यय[5] में गति में मंदी के कारण हुई। राजकोषीय समेकन[6] का पालन करते हुए, केंद्र सरकार ने वर्ष

सारणी III.2: उच्च आवृति संकेतक- मांग की सकारात्मक स्थिति

	संकेतक	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25	जन-26
शहरी मांग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	14.1	12.1	9.9	9.7	2.6	3.7	-2.5	-0.5	-2.5	3.5	7.0	-4.9	2.9
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	15.5	-10.3	6.3	1.6	-3.1	2.5	-0.8	0.9	5.8	10.7	19.7	26.6	7.2
ग्रामीण मांग	खुदरा वाहन बिक्री	6.6	-7.2	-0.7	2.9	5.4	4.8	-4.3	2.8	5.2	40.5	2.1	14.6	17.6
	खुदरा ट्रैक्टर बिक्री	5.2	-14.5	-5.7	7.6	2.8	8.7	11.0	30.1	3.6	14.2	56.5	15.8	22.9
	खुदरा दो-पहिया बिक्री	4.2	-6.3	-1.8	2.3	7.3	4.7	-6.5	2.2	6.5	51.8	-3.1	9.5	21.4

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणी: 1. सभी संकेतकों की व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है।
3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग उस डेटा सीरीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाता है।
4. जनवरी 2026 के लिए टोल संग्रह की वृद्धि दर के डेटा की गणना प्रतिदिन के डेटा को मिलाकर की जाती है।
5. खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री का डेटा दो पहिया, तीन पहिया, पैसेंजर वाहन, ट्रैक्टर, और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पर आधारित है।

स्रोत: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया; फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफ़एडीए); और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

[2] https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1770719506668_061eb34b-ec61-4890-9e61-73cc717b4d0b_Quarterly_Bulletin_PLFS_OCT-DEC_2025.pdf

[3] https://www.mospi.gov.in/uploads/latestReleases/latest_release_1771238931793_de83f41f-e1c3-4581-a99b-3432ee80881c_Monthly_Press_note_January_2026.pdf

[4] महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

[5] अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, ऋण-इतर पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व व्यय क्रमशः वर्ष 2025-26 (संशोधित अनुमान) के लक्ष्य का 71.9 प्रतिशत और 67.0 प्रतिशत रहे। इसकी तुलना में, पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये आंकड़े क्रमशः वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लक्ष्य का 46.3 प्रतिशत और 68.9 प्रतिशत थे।

[6] जैसा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी।

सारणी III.3: रोज़गार के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक

सूचकांक	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25	जन-26
बेरोज़गारी दर (पीएलएफ़एस: अखिल भारतीय)				5.1	5.6	5.6	5.2	5.1	5.2	5.2	4.7	4.8	5.0
बेरोज़गारी दर (पीएलएफ़एस: ग्रामीण)				4.5	5.1	4.9	4.4	4.3	4.6	4.4	3.9	3.9	4.2
बेरोज़गारी दर (पीएलएफ़एस: शहरी)				6.5	6.9	7.1	7.2	6.7	6.8	7.0	6.5	6.7	7.0
नौकरी जॉब्सपीक सूचकांक	3.9	4.0	-1.5	8.9	0.3	10.5	6.8	3.4	10.1	-9.3	23.5	13.2	3.4
पीएमआई रोज़गार: विनिर्माण	54.8	54.5	53.4	54.2	54.9	55.1	53.3	53.1	52.1	52.4	50.9	50.5	51.1
पीएमआई रोज़गार: सेवाएँ	56.3	56.2	52.5	53.9	57.1	55.1	51.4	52.2	51.9	51.4	51.6	49.8	50.8
एमजीएनआरईजीए: काम की मांग	14.4	2.8	2.2	-6.5	4.4	4.4	-12.3	-26.2	-27.1	-35.1	-32.0	-28.9	-25.7

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणी: 1. सभी पीएलएफ़एस संकेतक मौजूदा चालू सप्ताह के हैं और 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हैं।
2. नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक और मनरेगा में काम की मांग के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
3. हीटमैप अप्रैल 2023 से जनवरी 2026 तक के डेटा पर लागू किया गया है।
4. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के डेटा रेंज को रंग ग्रेडिएंट योजना में अनुवादित करता है, जिसमें लाल न्यूनतम मानों को और हरा संबंधित डेटा श्रृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
5. सभी पीएमआई मान सूचकांक रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। पीएमआई मान >50 का अर्थ है विस्तार, <50 का अर्थ है संकुचन और 50 का अर्थ है 'कोई परिवर्तन नहीं'। पीएमआई हीटमैप में, लाल न्यूनतम मान को, पीला 50 (या कोई परिवर्तन नहीं का मान) को और हरा प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।
6. एमजीएनआरईजीए को विपरीत पैमाने पर कोडित किया गया है - न्यूनतम को हरे रंग में और उच्चतम को लाल रंग में चिह्नित किया गया है।

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार; इन्फो एज; और एस एंड पी ग्लोबल।

2025-26 (संशोधित अनुमान) के लिए सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत ही बनाए रखा है, जो वर्ष के लिए बजट अनुमान के समान है।

केंद्रीय बजट 2026-27 ने राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की है, जबकि संवृद्धि-वर्धक पूंजीगत व्यय पर जोर बनाए रखा गया है। 2026-27 (बजट अनुमान) के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी) का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसमें बजटीय समेकन मुख्यतः राजस्व व्यय के युक्तिकरण और पूंजीगत व्यय को पूर्ववत् स्तर[7] पर बनाए रखने के माध्यम से

चार्ट III.1: सरकारी घाटा संकेतक (अप्रैल-दिसंबर)

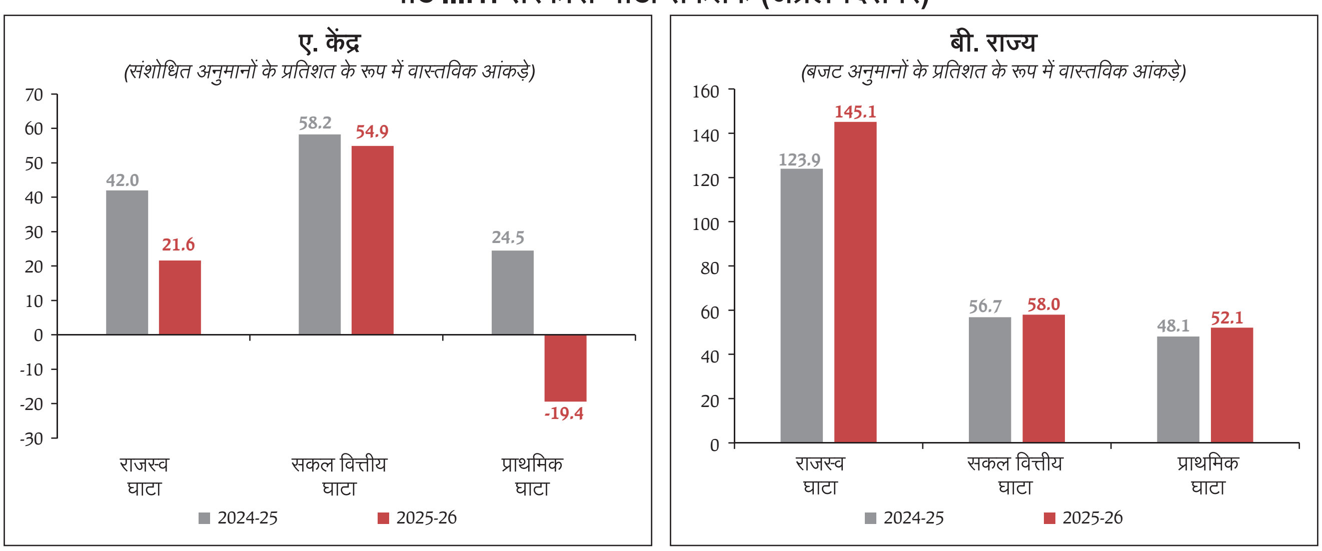

टिप्पणी: आंकड़े 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
स्रोत: नियंत्रक महालेखाधिकारी; भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और केंद्रीय सरकार के बजट दस्तावेज।

7 केंद्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता का एक सारांश संकेतक माने जाने वाले राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात के वर्ष 2026-27 में स्थिर रहने का अनुमान है।

प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। केंद्र का निवल कर राजस्व (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम बजटीय प्रावधानित किया गया है। नये आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के युक्तिकरण और आयकर नियमों के सरलीकरण जैसे कर सुधारों से मध्यम अवधि[8] में कर संग्रह में वृद्धि होने की अपेक्षा है। ऋण-इतर पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से वृद्धि का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो समर्पित रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी)[9] की स्थापना द्वारा सुगम बनाए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की आस्तियों के विनिवेश को दर्शाता है।

वित्त वर्ष के बजट अनुमानों (बीई) के अनुपात के रूप में, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान राज्यों के घाटे के संकेतक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक रहे (चार्ट III.1बी)। घाटे में यह वृद्धि मुख्य रूप से बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में हुई कमी के कारण हुई। राजस्व प्राप्तियों के भीतर, कर राजस्व के प्रमुख स्रोत[10] राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि दर में कमी आई। राज्यों का राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की संकुचन[11] के मुकाबले सुधार दर्ज किया गया।

सरकार ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनागढ़िया) की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों में निरंतरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित हुई है और केंद्र के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत बनाए रखी गई है। आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र में पुनर्संतुलन की सिफारिश की है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में राज्यों के योगदान को 10 प्रतिशत भार के साथ एक नए मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत की संवृद्धि महत्वाकांक्षाओं और राष्ट्रीय आर्थिक प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में राज्यों की भूमिका को मान्यता देने की आवश्यकता को दर्शाता है। जनसंख्या पर अधिक बल दिया गया है, जबकि क्षेत्रफल, आय अंतर और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को दिए गए भारों को कम कर दिया गया है। यद्यपि वन आवरण को दिया गया भार बनाए रखा गया है, लेकिन पूर्व के 'कर प्रयास' मानदंड को हटा दिया गया है (चार्ट III.2)।

चार्ट III.2: राज्यों के लिए क्षैतिज वितरण मानदंड

(प्रतिशत)

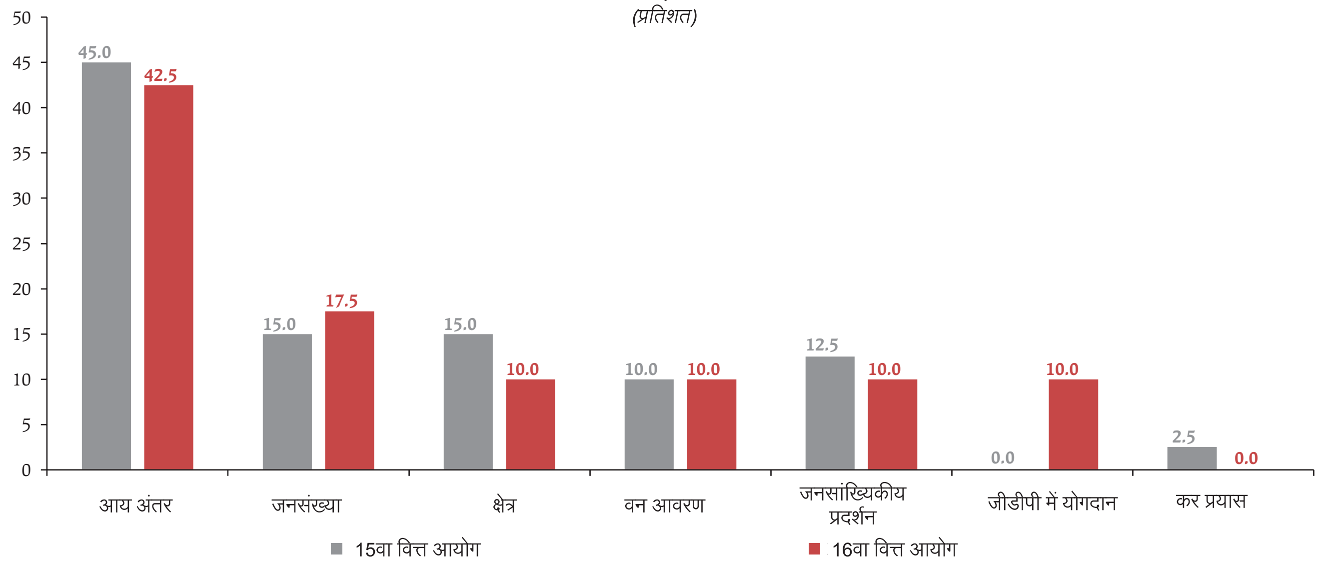

स्रोत: वित्त आयोग की रिपोर्टें।

[8] केंद्र के निवल कर राजस्व का वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.3 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है, जबकि वर्ष 2025-26 (संशोधित अनुमान) में यह जीडीपी का 7.5 प्रतिशत था।

[9] वर्ष 2026-27 में ऋण-इतर पूंजीगत प्राप्तियों में 84.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि वर्ष 2025-26 (संशोधित अनुमान) में यह वृद्धि 53.1 प्रतिशत थी।

[10] इस गिरावट में आंशिक रूप से अप्रैल 2025 में किए गए एक बार के ऋणात्मक समायोजन का प्रभाव था। यद्यपि वसूली में 2025-26 की दूसरी तिमाही से सुधार शुरू हुआ, परंतु बाद में 2025-26 की तीसरी तिमाही में यह मामूली हुई, जो जीएसटी स्लैब में कटौती के प्रभाव को दर्शाती है।

[11] केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' हेतु 2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ी हुई आवंटन राशि राज्यों के पूंजीगत व्यय को और बढ़ावा देगी।

व्यापार

2025-26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, पण्य वस्तु व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्वर्ण[12] रहा। अब तक 2025-26 के दौरान भारत का पण्य वस्तु निर्यात और आयात विस्तारित हुआ है।[13]

जनवरी 2026 में, आयात में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए पण्य वस्तु व्यापार घाटा बढ़ा (चार्ट III.3)[14]। चीन को निर्यात दोहरे अंक[15] में बना रहा, जबकि अमेरिका को निर्यात में संकुचन दर्ज किया गया। जनवरी में स्वर्ण और रजत दोनों के आयात में तीन अंकीय वृद्धि दर्ज की गई।

भारत ने एक महीने के अंदर अपने दो प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ ऐतिहासिक समझौते किए हैं। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने 27 जनवरी को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि भारत, यूरोपीय संघ से भारत निर्यातित 96.6 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्कों को समाप्त या कम करेगा, वहीं भारत के निर्यात का लगभग 99 प्रतिशत यूरोपीय संघ के बाजार को वरीयतापूर्ण पहुंच प्राप्त होगी। इस मुक्त व्यापार समझौते में गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक उपाय भी शामिल किए गए हैं।

7 फरवरी को घोषित अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के संबंध में, भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्कों को समाप्त या कम करने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने शुल्क दर को पूर्ववर्ती 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने और भारतीय कृषि निर्यात जैसे मसाले, चाय, कॉफी, फल, मेवे और संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए शून्य शुल्क पहुंच प्रदान

चार्ट III.3: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

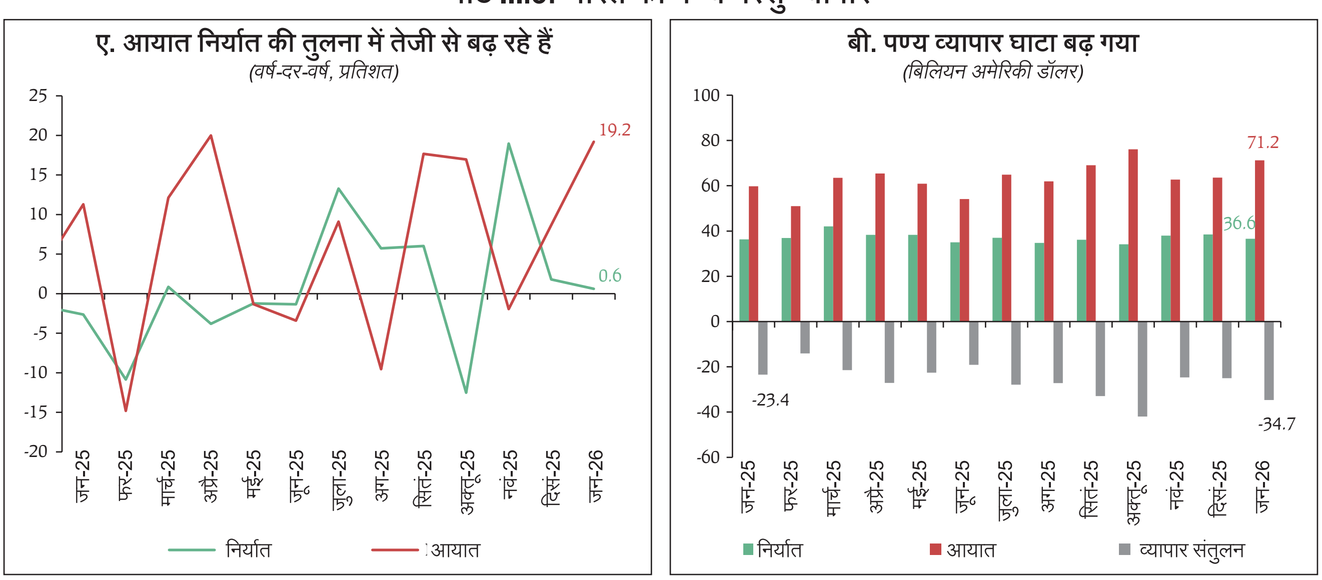

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस।

[12] वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान पण्य वस्तु व्यापार घाटा 283.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान यह 247.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[13] वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 30 प्रमुख वस्तुओं में से 16 वस्तुओं (जो निर्यात समूह का 54.9 प्रतिशत हिस्सा हैं) और 30 प्रमुख वस्तुओं में से 19 वस्तुओं (जो आयात समूह का 50.4 प्रतिशत हिस्सा हैं) में विस्तार दर्ज किया गया।

[14] जनवरी 2026 में पण्य व्यापार घाटा बढ़कर 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो जनवरी 2025 में 23.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जनवरी 2026 में पण्य निर्यात 36.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा [0.6 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)]। इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद और लौह अयस्क जैसे प्रमुख खंडों ने निर्यात को बढ़ावा दिया, जबकि रत्न और आभूषण, चावल, प्लास्टिक और लिनोलियम, सभी तरह के कपड़ों से बने बनी-बनाई वस्त्र, और तेल युक्त भोजन के कारण निर्यात में गिरावट आई। शीर्ष 20 प्रमुख गंतव्यों में से 11 को होने वाले निर्यात में विस्तार हुआ; यूएई, नीदरलैंड और चीन को निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अमेरिका, यूके और सिंगापुर को निर्यात में संकुचन हुआ। जनवरी 2026 में पण्य आयात 71.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा [19.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)]। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और अलौह धातुओं ने आयात में सकारात्मक योगदान दिया, जबकि कोयला, लोहा और इस्पात, दलहन, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, तथा जैविक और अजैविक रसायनों के कारण महीने के दौरान आयात में गिरावट आई। 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 14 देशों से आयात में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें चीन, यूएई और अमेरिका से आयात बढ़ा, जबकि रूस, इराक और दक्षिण कोरिया से आयात में कमी आई।

[15] जनवरी 2026 में चीन को निर्यात में 55.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान चीन को निर्यात में 38.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि रही।

करने पर सहमति जताई है। इन समझौतों के लागू होने से भारत में श्रम-गहन क्षेत्रों और निर्यात-उन्मुख उद्योगों को प्रमुख समर्थन प्राप्त होने की उम्मीद है।

दिसंबर माह में निवल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका मुख्य समर्थन व्यापारिक और सॉफ्टवेयर सेवाओं से मिला (चार्ट III.4)[16]।

समग्र पूर्ति

कृषि

रबी की बुवाई संपन्न हो गई है, जिसमें सभी प्रमुख फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। इसका समर्थन अनुकूल मृदा नमी, पर्याप्त जलाशय स्तर और अनुकूल तापमान से मिला है (चार्ट III.5)[17]। हालाँकि, जनवरी महीने में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है और फरवरी तथा मार्च के प्रारंभिक दिनों में तापमान में क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है, जिससे खड़ी फसलों पर इसके प्रभाव की निगरानी की आवश्यकता है (चार्ट III.6)[18]।

चार्ट III.4: निवल सेवा निर्यात में वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट III.5 मजबूत रबी बुवाई

(लाख हेक्टेयर, बायां स्केल; प्रतिशत, दायां स्केल)

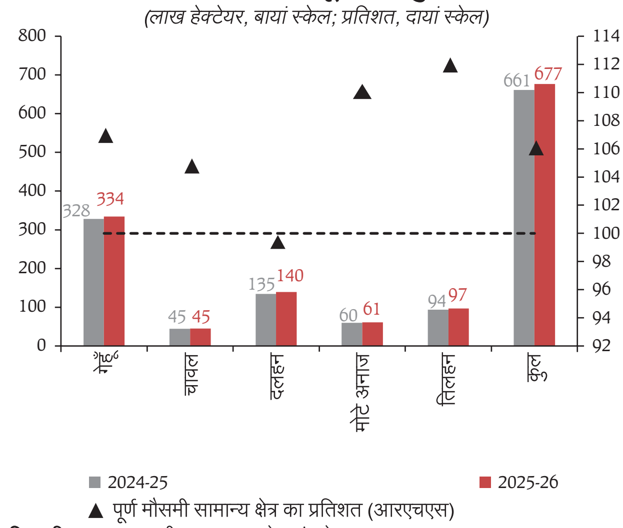

टिप्पणी: 1. 30 जनवरी, 2026 तक के आंकड़े।
2. क्षैतिज रेखा 100 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र कवरेज को दर्शाती है (आरएचएस)।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएँ।

उद्योग और सेवाएं

वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों[19] के त्रैमासिक परिणाम समग्र बिक्री

चार्ट III.6: जनवरी 2026 में तापमान की स्थितियाँ

(दीर्घकालिक औसत के प्रतिशत के रूप में)

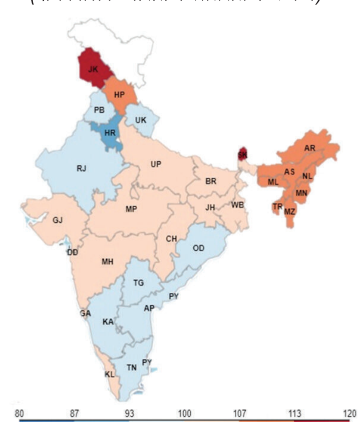

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े 31 जनवरी, 2026 तक के है।
2. वास्तविक तापमान सेल्सियस (°C) में दर्ज किया गया है और संबंधित दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से तुलना की गई है।
3. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में उनके एलपीए के क्रमशः 101 और 99 प्रतिशत तक औसत तापमान दर्ज किया गया।

स्रोत: आईएमडी; और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ।

[16] दिसंबर 2025 में निवल सेवा निर्यात बढ़कर 22.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो दिसंबर 2024 में 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था [18.3 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)]। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, निवल सेवा निर्यात बढ़कर 156.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2024 की अवधि में यह 135.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[17] 30 जनवरी, 2026 तक, रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र पूरे सीजन के सामान्य रकबे का 106.1 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक है।

[18] https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/extendedrangeforecast.php#. (18 फरवरी, 2026 को देखा गया)

[19] 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए 2,905 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ़) कंपनियों के परिणामों के आधार पर।

चार्ट III.7: बिक्री वृद्धि (सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियाँ)

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

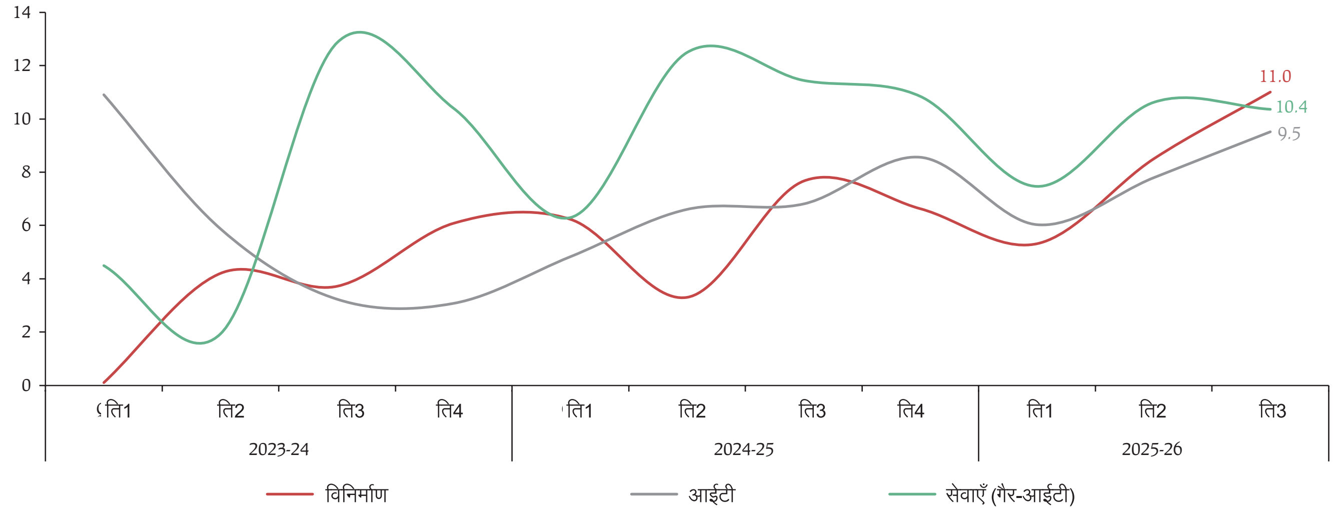

टिप्पणी: ये आंकड़े 2025-26 की तीसरी तिमाही में सूचीबद्ध 2,905 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों (1,678 विनिर्माण, 189 आईटी, और 812 गैर-आईटी सेवाएं) के परिणामों पर आधारित हैं।
स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ।

वृद्धि[20] में मजबूती का संकेत देते हैं। विनिर्माण कंपनियों ने दो अंकीय बिक्री वृद्धि दर्ज की है, जिसका समर्थन पेट्रोलियम उद्योग[21] में संकुचन के बावजूद ऑटोमोबाइल, विद्युत मशीनरी, खाद्य उत्पाद और अलौह धातु उद्योगों में बेहतर प्रदर्शन से मिला है। आईटी कंपनियों की बिक्री वृद्धि में सुधार हुआ, जबकि गैर-आईटी सेवाओं की बिक्री वृद्धि इस तिमाही के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रही (चार्ट III.7)।

विनिर्माण कंपनियों का परिचालन लाभ वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (तिमाही 3:2025-26) में वार्षिक आधार पर बढ़ा, जिसका मुख्य कारण अन्य व्ययों में वृद्धि का माध्यम होना रहा। हालाँकि, क्रमिक आधार पर परिचालन लाभ मार्जिन में कमी आई। सेवा क्षेत्र के भीतर, आईटी कंपनियों के लिए परिचालन लाभ वृद्धि में सुधार हुआ, जबकि गैर-आईटी सेवा कंपनियों के लिए यह मध्यम रहा। इसके बावजूद, इस तिमाहि के दौरान दोनों आईटी और गैर-आईटी कंपनियों के लिए परिचालन लाभ मार्जिन में क्रमिक विस्तार हुआ (चार्ट III.8)।

वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाहि के दौरान, सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की राजस्व वृद्धि मंद हुई, जबकि अन्य आय श्रेणी में वृद्धि के कारण निवल लाभ वृद्धि में बढ़ोतरी हुई (चार्ट III.9)[22]।

निवेश के मोर्चे पर, अप्रैल-दिसंबर 2025-26 के दौरान विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूंजीगत व्यय के उद्देश्यों हेतु जुटाई गई कुल निधि, 2019-20 से तुलनीय अवधि की तुलना में अधिक रही, जो सतत निवेश संबंधी आशावाद को दर्शाती है (चार्ट III.10)। यद्यपि तीसरी तिमाही के दौरान चयनित बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफ़आई) द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की कुल लागत पिछली तिमाही की तुलना में कम थी, फिर भी तीसरी तिमाही में स्वीकृत राशि कोविडोत्तर अवधि[23] की औसत से ऊपर रही, जो निवेश की मांग[24] की निरंतरता को रेखांकित करती है। इच्छित निवेश का बहुसंख्यक भाग बिजली, रसायन और निर्माण उद्योगों में केंद्रित रहा। पूंजीगत व्यय के उद्देश्यों से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रारंभिक

[20] 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान सकल विक्रय वृद्धि 9.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जो पिछली तिमाही में 8.0 प्रतिशत थी।

[21] पेट्रोलियम उद्योग को छोड़कर, विनिर्माण क्षेत्र के लिए विक्रय वृद्धि 12.7 प्रतिशत रही।

[22] अन्य आय में गैर-निधि आधारित बैंकिंग गतिविधियों से कमीशन आय, शुल्क, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी लेनदेन से अर्जन, निवेशों से लाभ और हानि (जिसमें पुनर्मूल्यन शामिल है), सहायक कंपनियों से लाभांश, और पूर्व में बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली शामिल है।

[23] वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान स्वीकृत राशि की तिमाही औसत ₹72,982 करोड़ थी।

[24] 2025-26 की तीसरी तिमाही में परियोजनाओं की कुल लागत ₹96,554 करोड़ थी, जबकि 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह ₹1,60,828 करोड़ थी। दूसरी तिमाही की पूंजीगत व्यय आंकड़े कुछ बड़ी परियोजनाओं के कारण असामान्य रूप से ज्यादा थे।

चार्ट III.8: सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की लाभप्रदता

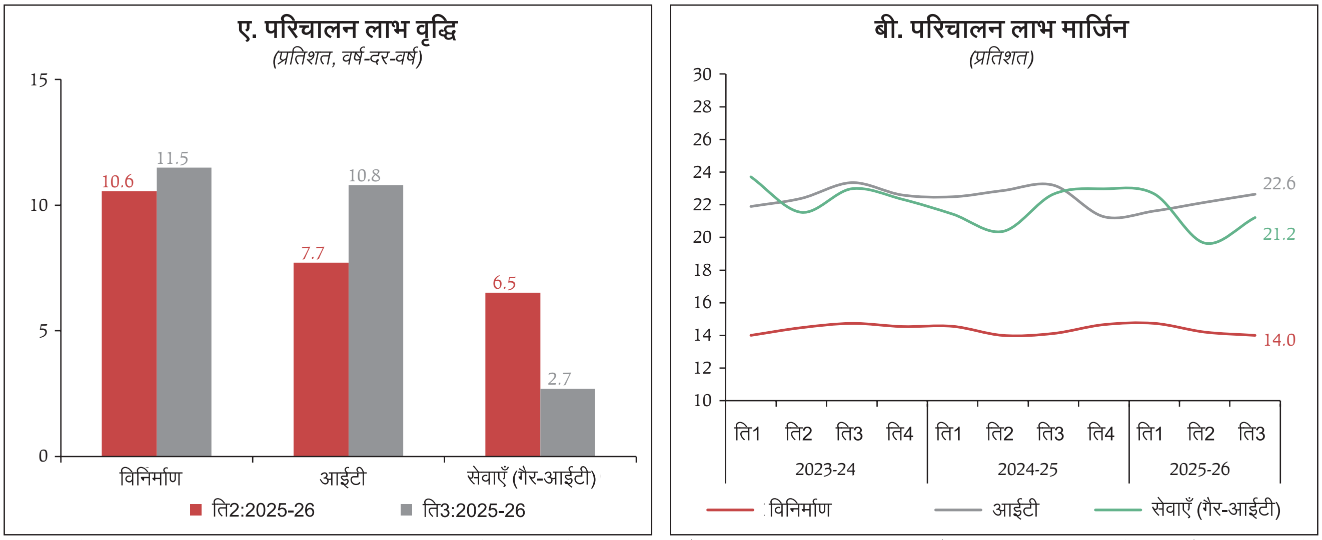

टिप्पणी: ये आंकड़े 2025-26 की तीसरी तिमाही में सूचीबद्ध 2,905 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों (1,678 विनिर्माण, 189 आईटी, और 812 गैर-आईटी सेवाएं) के परिणामों पर आधारित हैं।
स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ।

सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई निधि भी पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ी है।

औद्योगिक गतिविधियों के मासिक संकेतक

दिसंबर माह में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वार्षिक परिवर्तन के रूप में मापी गई औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि बढ़कर 26 महीने का उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जिसका मुख्य चालक विनिर्माण, खनन और बिजली—ये तीनों ही क्षेत्रों में दर्ज हुई मजबूत वृद्धि रही। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, छह खंडों में से चार खंडों में पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर में तेजी देखी गई। घरेलू मांग में मजबूती का संकेत देते हुए, अवसंरचना और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं दोहरे अंक की विस्तार के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खंड रहे। यद्यपि पूंजीगत वस्तुओं के खंड में वृद्धि दर में कुछ नरमी दर्ज की गई,

चार्ट III.9: सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

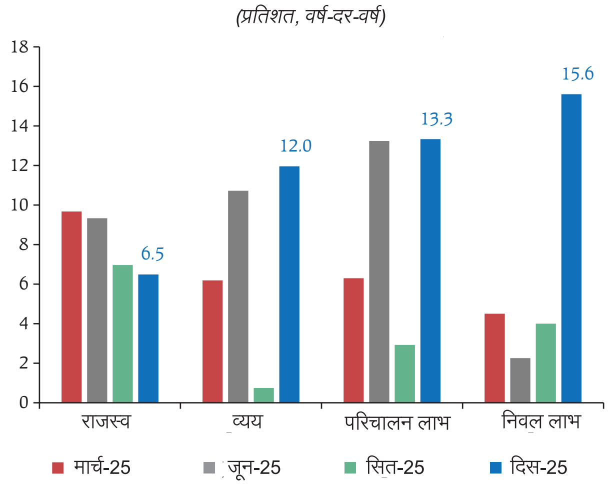

टिप्पणी: यह 584 कंपनियों के नमूने पर आधारित है, जो सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 93.4 प्रतिशत बनाती हैं।
स्रोत: सीएमआईई प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ।

चार्ट III.10: निजी कंपनियों की निवेश योजनाएँ

(हजार करोड़ रुपए)

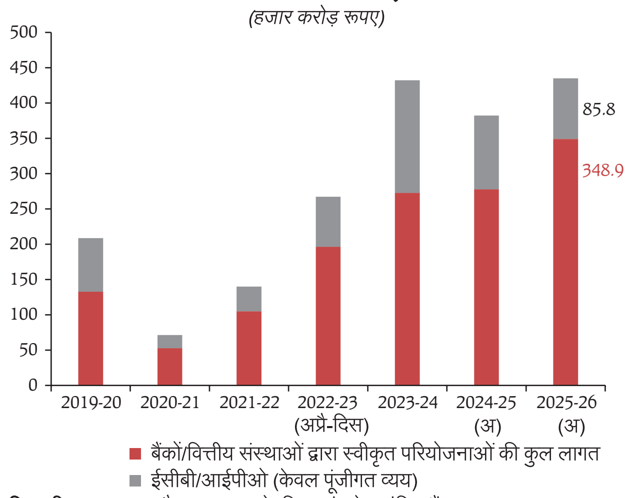

टिप्पणी: 2024-25 और 2025-26 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से परियोजना वित्त पर एकत्रित आंकड़े; और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ।

फिर भी यह ऊंचे स्तर पर बनी रही, जो निवेश में पुनरुत्थान को दर्शाती है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में दिसंबर महीने में चार महीने का उच्चतम विकास दर दर्ज किया गया, जिसका नेतृत्व इस्पात और सीमेंट में मजबूत वृद्धि तथा बिजली उत्पादन में सुधार ने किया।

जनवरी माह में औद्योगिक गतिविधियों के उच्च-आवृत्ति संकेतक मजबूत बने रहे। नए आदेशों, उत्पादन और रोजगार में सुधार के समर्थन से विनिर्माण पीएमआई में मजबूती आई। सभी खंडों में, जनवरी में वाहन उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, यद्यपि यह गति कुछ धीमी रही, जो जीएसटी दरों में कटौती के कारण उत्पादन में पहले हुई तेजी के बाद कुछ सामान्यीकरण को दर्शाती है (सारणी III.4)।

केंद्रीय बजट 2026-27 ने जलवायु-अनुकूल अवसंरचना के निर्माण हेतु स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है, जो भारत के हरित संक्रमण को और गति प्रदान करेगा। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए, इसमें कठिन-न्यूनीकरण योग्य उद्योगों जैसे कि बिजली, इस्पात, सीमेंट, शोधनागार और रसायन में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। एक प्रमुख रणनीतिक विनिर्माण प्रोत्साहन के रूप में और वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को उन्नत करने हेतु, 1,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की शुरुआत की गई है।

सारणी III.4: उद्योग के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक मजबूत बने रहे

संकेतक	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25	जन-26
आईआईपी-हेडलाइन	5.2	2.7	3.9	2.6	1.9	1.5	4.3	4.1	4.6	0.5	7.2	7.8	
आईआईपी-विनिर्माण	5.8	2.8	4.0	3.1	3.2	3.7	6.0	3.8	5.6	2.0	8.5	8.1	
आईआईपी-पूंजीगत वस्तु	10.2	8.2	3.6	14.0	13.3	3.0	6.8	4.5	5.4	2.1	10.1	8.1	
पीएमआई विनिर्माण	57.7	56.3	58.1	58.2	57.6	58.4	59.1	59.3	57.7	59.2	56.6	55.0	55.4
पीएमआई एक्सपोर्ट ऑर्डर	58.6	56.3	54.9	57.6	56.9	60.6	57.3	56.1	56.5	54.7	54.1	54.0	54.1
पीएमआई विनिर्माण, फ्यूचर आउटपुट	65.1	64.9	64.4	64.6	63.1	62.2	57.6	60.5	64.8	62.3	57.1	56.9	56.4
आठ प्रमुख सूचकांक	5.1	3.4	4.5	1.0	1.2	2.2	3.7	6.5	3.3	-0.1	2.1	3.7	
विद्युत निर्माण: परंपरागत	-1.3	2.4	4.8	-1.8	-8.2	-6.1	-0.8	1.0	0.8	-10.6	-5.0	4.3	1.9
विद्युत निर्माण: नवीकरणीय	31.9	12.2	25.2	28.0	18.2	28.7	26.4	22.7	16.4	21.4	22.9	18.0	
ऑटोमोबाइल उत्पादन	9.4	2.3	6.5	-1.7	5.2	1.2	10.7	8.1	10.8	-2.8	22.3	37.1	15.0
यात्री वाहन उत्पादन	3.7	4.5	11.2	10.8	5.4	-1.8	0.1	-4.1	16.1	9.8	22.8	23.1	5.6
ट्रैक्टर उत्पादन	23.7	-7.8	18.5	20.5	9.1	9.8	11.5	9.4	23.0	13.0	37.5	57.9	14.6
दो-पहिए उत्पादन	10.3	1.6	5.6	-4.1	4.7	1.4	12.3	10.0	9.8	-5.6	20.9	39.9	16.1
तीन-पहिए उत्पादन	16.2	6.5	6.0	4.1	16.9	8.6	24.0	15.8	15.9	15.9	55.4	39.6	33.2
कच्चा इस्पात उत्पादन	7.4	6.0	8.5	9.3	11.0	12.6	13.8	12.8	13.7	8.9	10.8	5.3	4.1
तैयार इस्पात उत्पादन	6.7	6.7	10.0	6.6	7.0	10.9	13.8	13.8	14.0	7.2	11.8	2.0	3.2
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	15.5	-0.5	8.6	24.5	15.7	3.4	13.3	0.2	12.7	8.6	13.1	13.2	7.2

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।

2. हीट मैप प्रत्येक संकेतक की डेटा श्रेणी को कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदल देता है, जहां लाल सबसे निम्न मान को दर्शाता है और हरा संबंधित डेटा श्रृंखला के सबसे उच्च मान को दर्शाता है।

3. हीटमैप उन डेटा पर लागू किया गया है जो अप्रैल 2023 से लेकर उस नवीनतम महीने तक उपलब्ध हैं जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

4. सभी पीएमआई मानों को सूचकांक रूप में रिपोर्ट किया गया है। पीएमआई मान > 50 होने पर विस्तार, 50> होने पर संकुचन और =50 होने पर 'कोई परिवर्तन नहीं' का संकेत मिलता है। पीएमआई हीट मैप में लाल सबसे निम्न मान को दर्शाता है, पीला 50 (या अपरिवर्तित मान) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); एस&पी ग्लोबल; केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफेक्चर्र्स (एसआईएएम); आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार; संयुक्त संयंत्र समिति; वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय; और ट्रैक्टर एंड मेकेनिजेशन एसोशिएशन

बजट में 2035 तक परमाणु परियोजनाओं के लिए आवश्यक आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट को भी बढ़ाया गया है।

पिछले दो वर्षों में, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो वर्ष 2024 में 'सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' की शुरुआत के साथ मजबूत हुई है। इसके तहत दिसंबर 2025 तक छत सौर तैनाती बढ़कर 20 लाख से अधिक प्रणालियों तक पहुंच गई है, जिससे लगभग 26 लाख घरेलू परिवारों को लाभ हुआ है (चार्ट III.11)।[25] नवीकरणीय ऊर्जा को और भी गति प्रदान करने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में सौर घटकों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए सीमा शुल्क प्रोत्साहन के माध्यम से नीतिगत सहायता प्रदान की गई है।

चार्ट III.11: स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में मजबूत वृद्धि

(गिगावाट, बायां मान; प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष, दायाँ मान)

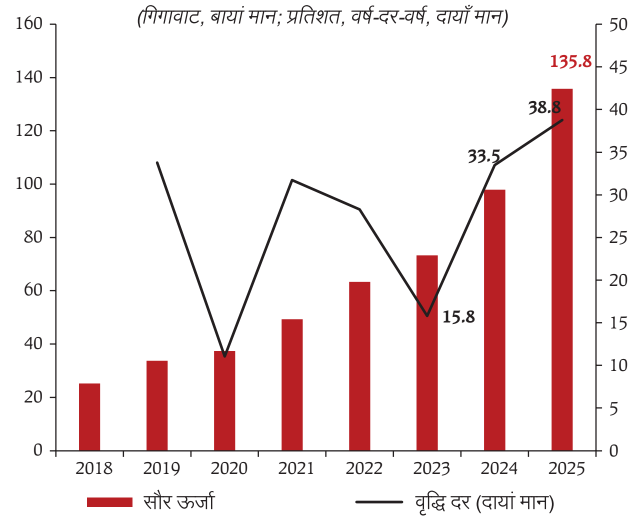

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।

सेवा गतिविधियों के मासिक संकेतक

जनवरी महीने में भारत के सेवा क्षेत्र ने अपनी स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखा। बेहतर माल ढुलाई भाव और प्रतिस्थापन खरीदारी द्वारा संचालित होकर, वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री ने दोहरे अंकों वाली वृद्धि को बनाए रखा। बंदरगाह माल यातायात ने भी वृद्धि की गतिशीलता को बनाए रखा (सारणी III.5)।

सारणी III.5: सेवाओं में मजबूत वृद्धि जारी रही

संकेतक	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25	जन-26
पीएमआई सेवाएँ	56.5	59.0	58.5	58.7	58.8	60.4	60.5	62.9	60.9	58.9	59.8	58.0	58.5
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा ट्रेफिक	11.1	7.7	6.8	13.0	5.0	3.4	5.5	7.7	7.3	9.7	7.5	6.0	6.8
घरेलू हवाई मालवाहक	6.9	-2.5	4.9	16.6	2.3	2.6	4.8	7.1	2.8	-2.3	20.5	4.3	
अंतरराष्ट्रीय हवाई मालवाहक	7.1	-6.3	3.3	8.6	6.8	-1.2	4.2	4.5	2.3	-2.3	12.7	12.6	
बंदरगाह माल यातायात	7.6	3.6	13.3	7.0	4.3	5.6	4.0	2.5	11.5	11.9	14.5	12.8	7.6
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	8.2	-8.6	2.7	-1.0	-3.7	6.6	0.2	8.6	2.7	21.1	17.0	24.6	15.1
इस्पात खपत	9.0	10.9	13.6	6.0	8.1	9.3	7.3	10.0	8.9	2.4	6.0	3.4	
सीमेंट उत्पादन	14.3	10.7	12.2	6.3	9.7	8.2	11.6	5.4	5.0	5.2	14.6	13.5	

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों के लिए (पीएमआई को छोड़कर) वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।

2. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के डेटा रेंज को रंग ग्रेडिएंट योजना में बदल देता है, जिसमें लाल सबसे कम मान और हरा संबंधित डेटा श्रृंखला के उच्चतम मान का प्रतिनिधित्व करता है।

3. हीटमैप अप्रैल 2023 से उस नवीनतम महीने तक के डेटा पर लागू किया गया है, जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

4. दिसंबर 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री ट्रैफिक का वृद्धि दर दैनिक डेटा को समेकित करके गणना की गई है।

5. सभी पीएमआई मान सूचकांक रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। पीएमआई का मान > 50 विकास को दर्शाता है, <50 संकुचन को दर्शाता है और =50 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है। पीएमआई हीटमैप्स में, लाल सबसे कम मान का, पीला 50 (या कोई परिवर्तन नहीं मान) का और हरा प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में सबसे उच्च मान का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: फेडेरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोशिएशन (एफएडीए); इंडियन पॉर्ट्स असोशिएशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; और एस&पी ग्लोबल।

[25] https://w.ww.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222476®=3&lang=1

मुद्रास्फीति

12 फरवरी, 2026 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अद्यतन आधार (2024=100) के साथ नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला जारी की, जिसमें जनवरी 2026 के लिए वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) मुद्रास्फीति का आंकड़ा भी शामिल था। इस अद्यतन श्रृंखला में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर भारों का पुनरीक्षण किया गया है। मदों के भारों में पुनरीक्षण के अलावा, सीपीआई 2024 श्रृंखला में वर्गीकरण में ऐसे परिवर्तन शामिल किए गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के व्यक्तिगत उपभोग वर्गीकरण (सीओआईसीओपी) 2018 ढांचे के अनुरूप हों (अनुलग्नक बॉक्स ए)।

सीपीआई 2024 आधार वर्ष श्रृंखला के आधार पर, जनवरी में सकल मुद्रास्फीति[26] 2.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही। खाद्य, ईंधन और समग्र (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति क्रमशः 2.1 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत रही। कीमती धातुओं को छोड़कर, समग्र मुद्रास्फीति कम होकर 1.9 प्रतिशत रही, जो यह दर्शाता है कि अंतर्निहित मूल्य दबाव अपेक्षाकृत नियंत्रित बने हुए हैं (सारणी III.6)।

जनवरी में सकल मुद्रास्फीति में अधिकांश भाग समग्र मुद्रास्फीति का रहा, जिसके बाद खाद्य और ईंधन[27] का स्थान था। खाद्य मदों के भीतर, फलों और मेवों, दूध, डेयरी उत्पादों और अंडों, मांस तथा तेलों और वसा से मुख्य सकारात्मक योगदान आया; जबकि सब्जियों और दालों ने अधोगामी दबाव डाला। गैर-खाद्य मदों में, सोने/हीरे/प्लैटिनम के आभूषणों ने सकल मुद्रास्फीति में लगभग 31 आधार बिंदुओं का योगदान दिया[28]।

जनवरी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत रही। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर, मुद्रास्फीति 0.1 प्रतिशत से 4.9 प्रतिशत के बीच रही, जिसमें अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रही (चार्ट III.12)।

सारणी III.6: नए सीपीआई (2024=100) श्रृंखला के आधार पर जनवरी 2026 में वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति

क्र. सं.	विभाग	मुद्रास्फीति *(प्रतिशत)*
1	खाद्य और पेय पदार्थ	2.1
2	पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	2.9
3	कपड़े और फुटवियर	3.0
4	आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन	1.5
5	साज-सज्जा, घरेलू उपकरण और नियमित घरेलू देखभाल	1.4
6	स्वास्थ्य	2.2
7	परिवहन	0.1
8	सूचना और संचार	0.2
9	मनोरंजन, खेल और संस्कृति	2.3
10	शिक्षा सेवाएँ	3.4
11	रेस्टोरेंट और आवास सेवाएँ	2.9
12	व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएँ और सेवाएँ	19.0
13	कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर)	3.4
14	कीमती धातुओं को छोड़कर कोर	1.9

स्रोत: एनएसओ।

17 फरवरी, 2026 तक के उच्च-आवृत्ति खाद्य मूल्य आंकड़े अनाज की कीमतों में कुछ दबाव का संकेत देते हैं। दालों के वर्ग में,

चार्ट III.12: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण: जनवरी 2026

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

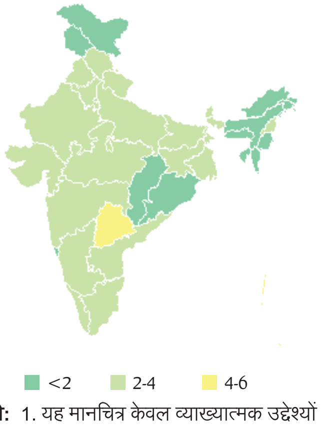

मुद्रास्फीति सीमा	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
<2	11
2-4	23
4-6	2

टिप्पणी: 1. यह मानचित्र केवल व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए है।
2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में क्रमशः 4.3 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति अनुभव की गई।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

[26] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 फरवरी 2026 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

[27] समग्र मुद्रास्फीति में कोर समूह का योगदान लगभग 71 प्रतिशत रहा। खाद्य मुद्रास्फीति का योगदान लगभग 28.3 प्रतिशत था, जबकि ईंधन का योगदान केवल लगभग 0.7 प्रतिशत था।

[28] सोने में वर्ष-दर-वर्ष 46.8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

चार्ट III.13: फरवरी में सब्जियों को छोड़कर खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई

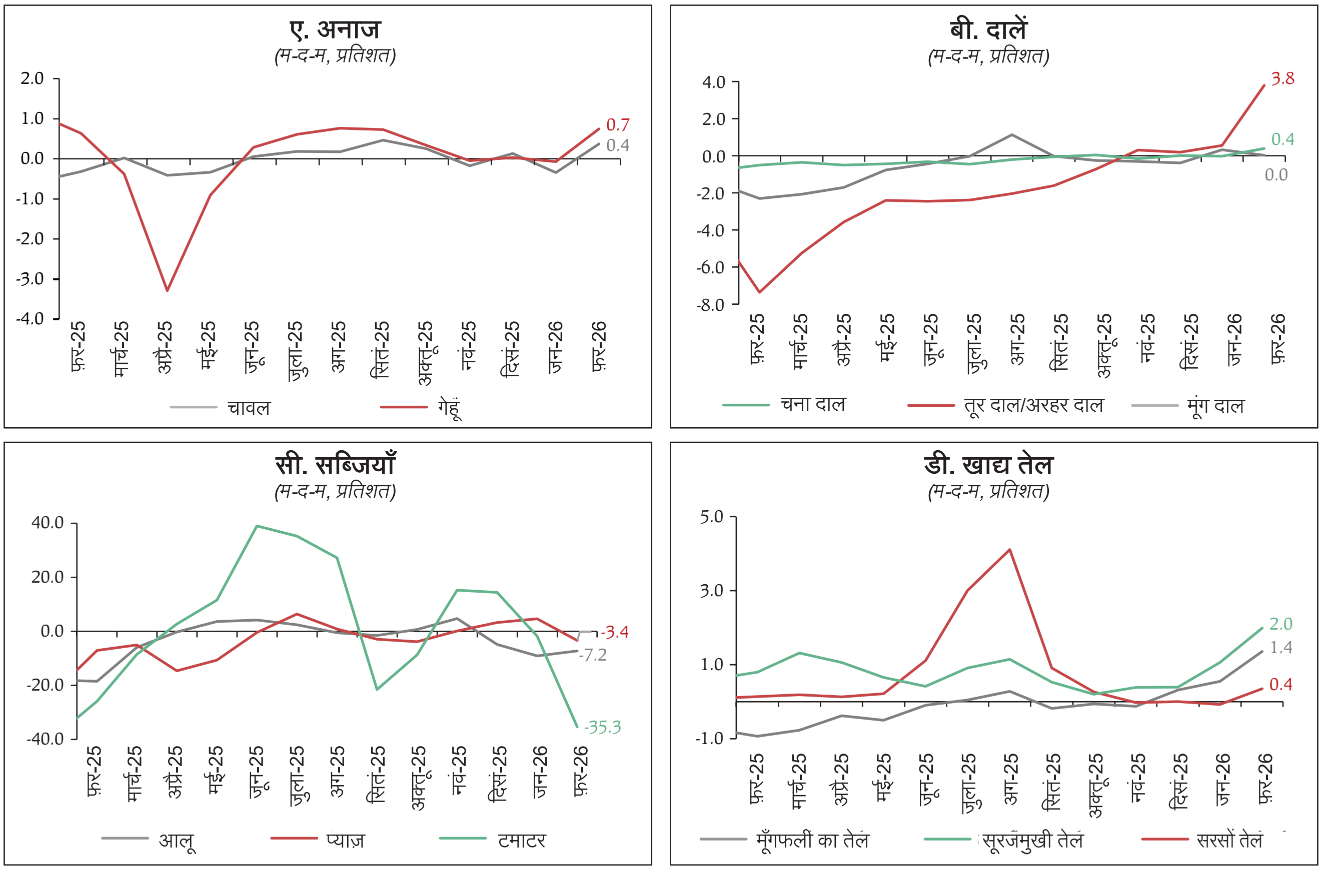

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ गणनाएँ।

चना, मूंग और तुर/अरहर दाल में व्यापक स्तर पर वृद्धि स्पष्ट है। खाद्य तेलों में सूरजमुखी तेल, सरसों तेल और मूंगफली तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, प्रमुख सब्जियों में फरवरी महीने में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में नरमी आई है (चार्ट III.13)।

फरवरी में (17 तारीख तक) पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि केरोसिन की कीमतों में गिरावट आई (सारणी III.7)।

जनवरी में, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के पीएमआई में इनपुट कीमतों की वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखी गई। विनिर्माण क्षेत्र में इनपुट लागत चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन दीर्घकालिक औसत से नीचे रही। विनिर्माण कंपनियों के लिए आउटपुट कीमतों की वृद्धि दर में कमी आई, जबकि सेवा कंपनियों के लिए यह बढ़ गई (चार्ट III.14)।

सारणी III.7: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		फर-25	जन-26	फर-26^	जन-26	फर-26^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.1	101.2	101.2	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	90.5	90.5	90.5	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी)	₹/लीटर	46.4	45.1	44.1	-7.4	-2.2
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.3	863.3	863.3	0.0	0.0

^: 1-17 फरवरी, 2026 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: 1. केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.14: पीएमआई - इनपुट और आउटपुट मूल्य

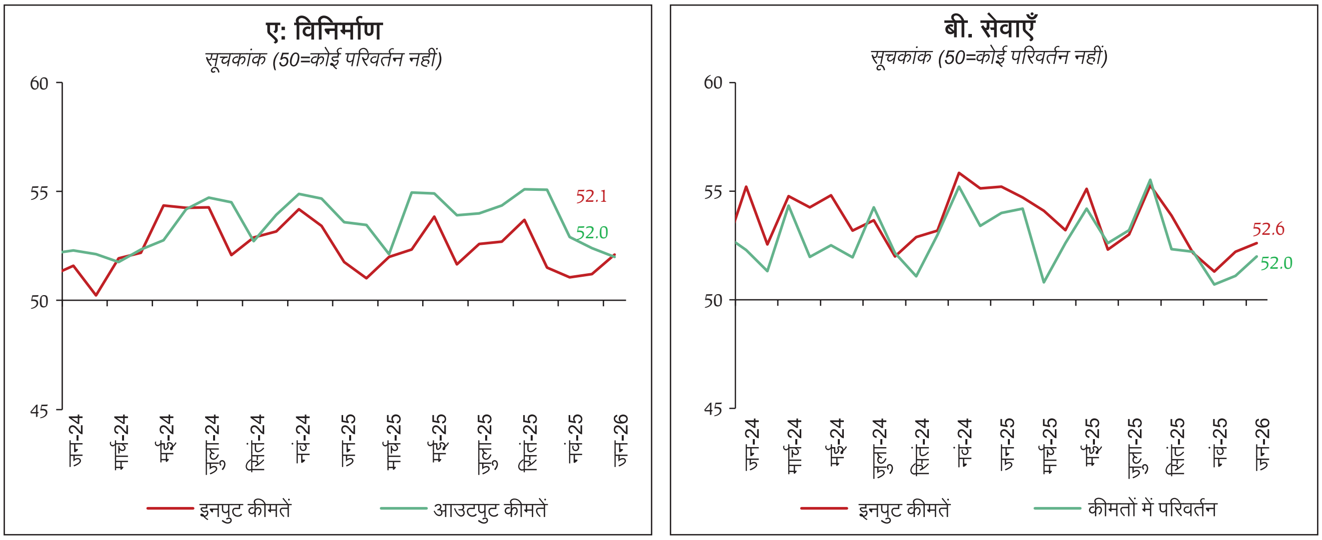

टिप्पणी: 50 का लेवल एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं दिखाता है, और 50 से ऊपर की रीडिंग बढ़ोतरी दिखाती है और इसका विपरीत भी होता है।
स्रोत: एसएंडपी।

IV. वित्तीय परिस्थितियां

कुल मिलाकर, जनवरी के दूसरे पखवाड़े से लेकर अब तक (17 तारीख़ तक) वित्तीय परिस्थितियों में कुछ सख्ती देखी गई, जिसकी मुख्य वजह कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार में आई सापेक्षिक सख्ती थी (चार्ट IV.1)।

जनवरी के दूसरे पखवाड़े में प्रणाली में चलनिधि में मामूली अधिशेष थी, जो महीने के आखिर और फरवरी में बढ़ गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से त्वरित सरकारी खर्च और आरबीआई द्वारा चलनिधि बढ़ाने वाले उपायों की एक श्रृंखला के कारण हुई थी। रिज़र्व बैंक ने जनवरी के दूसरे पखवाड़े में अल्पकालिक चलनिधि की कमी[29] को दूर करने के लिए छह परिवर्ती रेपो दर (वीआरआर) नीलामी आयोजित कीं। रिज़र्व बैंक ने ₹1.5 लाख करोड़ के खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के अंतर्गत खरीद के लिए नीलामी और 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 3-साल

चार्ट IV.1: वित्तीय परिस्थितियों में सख्ती
(2012 से औसत से मानक विचलन)

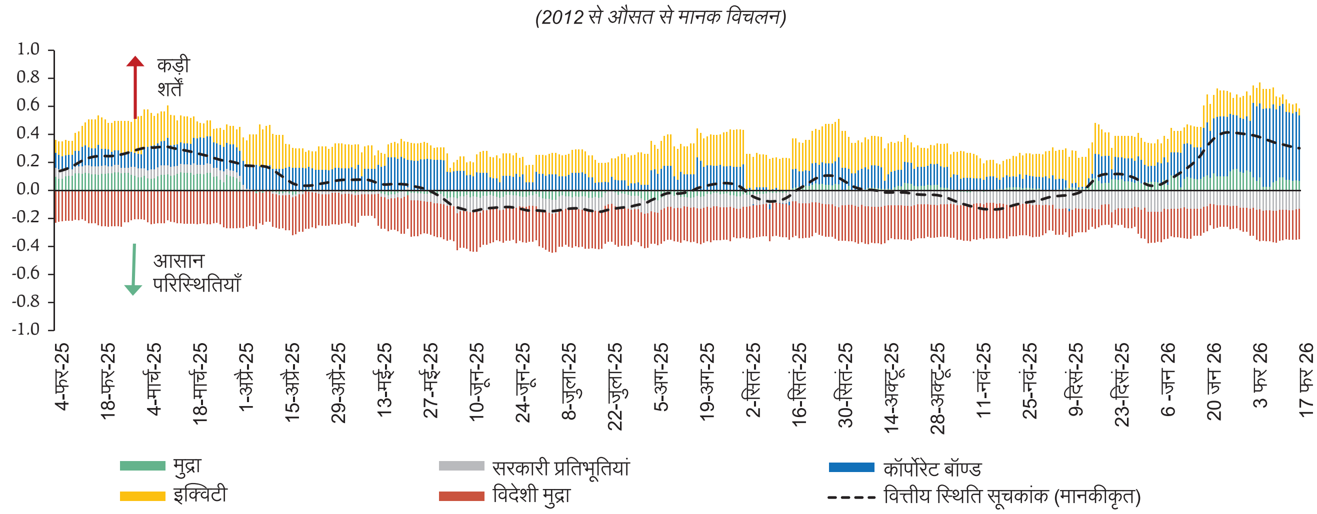

टिप्पणी: वित्तीय स्थिति सूचकांक अपने ऐतिहासिक औसत के आधार पर एक मैट्रिक्स देता है; इस मामले में, शून्य मान उस वित्तीय प्रणाली से मेल खाती है जो सूचकांक में शामिल सभी वित्तीय संकेतक के ऐतिहासिक औसत स्तर पर काम कर रहा है। परिणाम दिखाने के लिए, मानक सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[29] जनवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 से 8 दिन की परिपक्वता अवधि वाली 4 वीआरआर नीलामियां आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में दीर्घकालिक चलनिधि लाने हेतु दो 90-दिवसीय वीआरआर नीलामियां भी आयोजित की गईं, जिनमें उधार ली गई राशि को समय से पूर्व चुकाने का विकल्प भी प्रदान किया गया था।

चार्ट IV.2 : बढ़ती हुई चलनिधि अधिशेष

(₹ लाख करोड़)

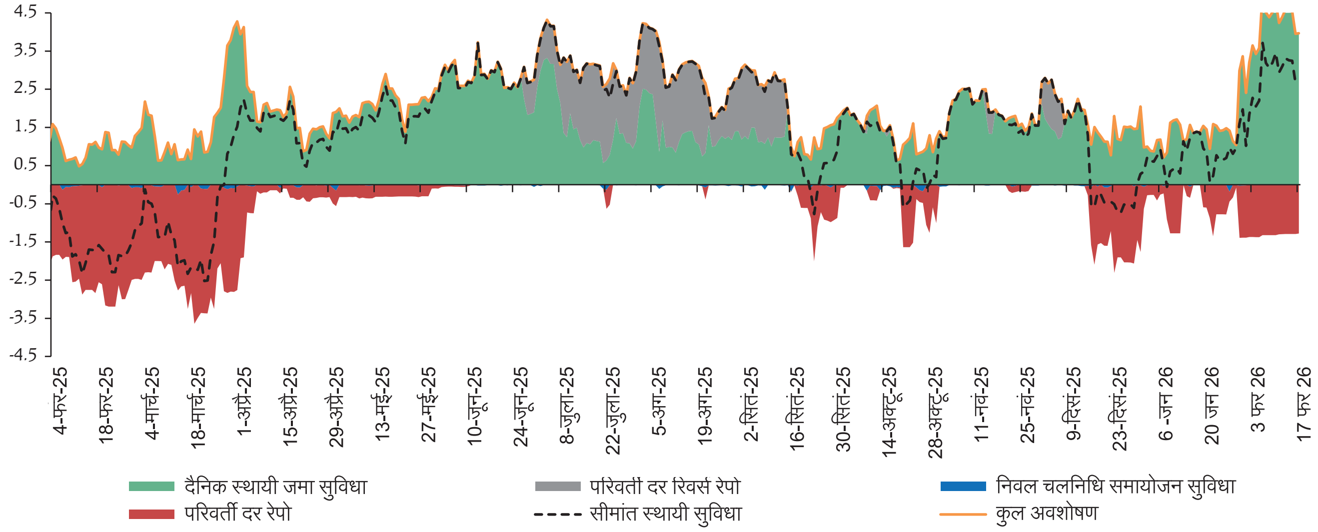

स्रोत: आरबीआई।

की अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी भी आयोजित की।[30]

पर्याप्त चलनिधि के कारण 16 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत औसत निवल अवशोषण पिछले एक महीने की अवधि की तुलना में बढ़ गया (चार्ट IV.2)[31]; साथ ही, बैंकों द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के इस्तेमाल में भी तेज़ी से वृद्धि दर्ज की गई। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का उपयोग मोटे तौर पर स्थिर रहा, यह इंगित करता है कि दैनिक चलनिधि असंगतियां नगण्य थीं और उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया।[32]

मुद्रा बाजार

जनवरी के दौरान, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) आम तौर पर नीतिगत दायरे के ऊपरी आधे हिस्से में बना रहा। यह माल एवं सेवा कर के बहिर्वाह और संचलनगत मुद्रा में वृद्धि के कारण चलनिधि पर बने दबाव को दर्शाता है। महीने के अंत में सरकारी खर्च और आरबीआई के चलनिधि संवर्धन उपायों के कारण फरवरी में डब्ल्यूएसीआर रेपो दर से नीचे रहा (चार्ट IV.3ए)।[33] संपार्श्विक खंडों में रात्रिपर्यंत दरें – जिन्हें बेंचमार्क सिक्योर्ड रात्रिपर्यंत रुपया दर (एसओआरआर) से मापा जाता है – आम तौर पर असंपार्श्विक दर के साथ-साथ ही चले। मुद्रा बाजार में, जनवरी में खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर ब्याज दरें बढ़ीं, जो चलनिधि अधिशेष में कमी, मोचन के एक साथ होने से आपूर्ति की वृद्धि और वर्ष के अंत में आम तौर पर होने वाले मौसमी दबाव को दिखाता है (चार्ट IV.3बी)।[34] इसके परिणामस्वरूप, मुद्रा बाजार में

[30] भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जनवरी, 2026, 29 जनवरी, 2026 और 5 फरवरी, 2026 को तीन किश्तों में प्रत्येक ₹0.5 लाख करोड़ की कुल ₹1.5 लाख करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खुले बाजार परिचालन खरीद नीलामियाँ आयोजित कीं। सभी नीलामियों में अच्छी मांग देखी गई। 4 फरवरी, 2026 को आयोजित 3 वर्ष की अवधि के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी में सूचित राशि से लगभग दो गुना बोली प्राप्त हुई।

[31] समग्र रूप से 16 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत निवल अवशोषण ₹1.89 लाख करोड़ रहा, जो पिछले एक माह की अवधि के दौरान ₹0.08 लाख करोड़ की तुलना में अधिक था।

[32] स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसत शेष राशि 16 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान पिछले एक माह की अवधि के ₹1.29 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.88 लाख करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा से उधारी औसतन ₹0.01 लाख करोड़ रही, जो पिछले एक माह की अवधि के औसत ₹0.02 लाख करोड़ से मामूली रूप से कम थी।

[33] औसतन, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) 16 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान पिछले एक माह की अवधि में 5.40 प्रतिशत से घटकर 5.21 प्रतिशत हो गई।

[34] 16 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 की अवधि की तुलना में 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के दौरान 3-महीने के खजाना बिलों पर औसत प्रतिफलों में 9 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि हुई, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3-महीने के वाणिज्यिक पत्रों और 3- महीने के जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर प्रतिफलों में क्रमशः 79 और 81 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट IV.3: डब्ल्यूएसीआर रेपो रेट से नीचे चला गया; मुद्रा बाजार स्प्रेड बढ़ा

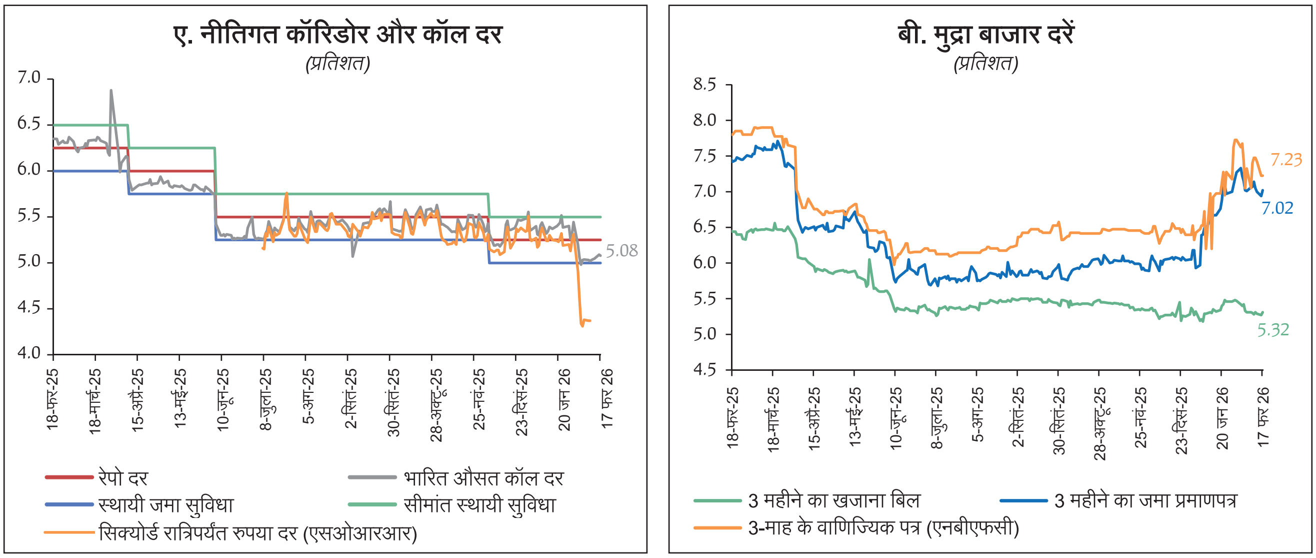

स्रोत: आरबीआई; और ब्लूमबर्ग।

औसत जोखिम प्रीमियम (3-महीने के वाणिज्यिक पत्र और 91-दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल के बीच का प्रसार) में भी वृद्धि देखी गई।[35] फरवरी में, हालांकि प्रणाली चलनिधि की स्थिति में सुधार हुई है, सीपी और सीडी दरें ऊंची बनी हुई हैं।

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

नियत आय खंड में, 19 जनवरी और 17 फरवरी के बीच, प्रतिफल वक्र के दीर्घकालिक हिस्से को छोड़कर अन्य अवधि संरचना में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर मिलने वाले प्रतिफल में गिरावट आई(चार्ट IV.4ए और बी)।[36, 37]

चार्ट IV.4: जी-सेक प्रतिफल में बढ़ोतरी

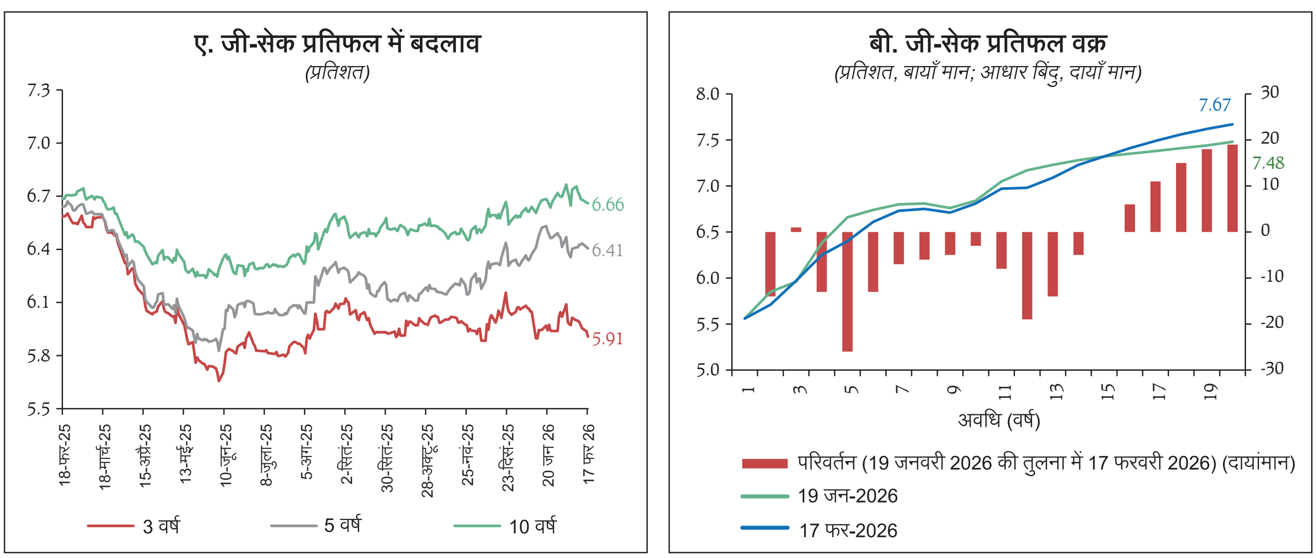

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

[35] यह पिछले एक माह की अवधि में 125 आधार अंक (बीपीएस) से बढ़कर 16 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान 195 आधार अंक हो गया।

[36] बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (6.48 जीएस 2035) पर प्रतिफल 15 जनवरी 2026 को 6.65 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 17 फरवरी 2026 को 6.66 प्रतिशत हो गई।

[37] वर्ष 2026-27 के लिए सकल बाजार उधारी में वृद्धि कर ₹17.20 लाख करोड़ किए जाने की बजट घोषणा के बाद, 10-वर्षीय प्रतिफल 2 फरवरी, 2026 को पिछले दिन के 6.70 प्रतिशत से बढ़कर 6.77 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त के आखिर के बाद से इसमें हुई सबसे तीव्र अंतर्दिवसीय वृद्धि थी।

सारणी IV.1: कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफलों में मजबूती

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	दिसंबर 16, 2025 – जनवरी 14, 2026	जनवरी 16, 2026 – फरवरी 16, 2026	परिवर्तन	दिसंबर 16, 2025 – जनवरी 14, 2026	जनवरी 16, 2026 – फरवरी 16, 2026	परिवर्तन
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
(i) एएए (1-वर्ष)	7.12	7.53	41	151	181	30
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.20	7.31	11	122	122	0
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.34	7.50	16	80	91	11
(iv) एए (3-वर्ष)	8.18	8.28	10	221	221	0
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	11.79	11.91	12	581	582	1

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए।

कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार

अलग-अलग अवधि और रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉण्ड पर प्रतिफलों में वृद्धि हुई और सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में उनके प्रसार में सामान्य विस्तार हुआ (सारणी IV.1)।

कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल सभी अवधियों और रेटिंग श्रेणियों में बढ़ी हैं, और सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में उनके प्रसार में सामान्यतः विस्तार हुआ है (सारणी IV.1)। नवंबर की तुलना में दिसंबर में नए कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने में वृद्धि हुई। संचयी आधार पर, चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हैं, जिसका कारण कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि और बैंक ऋण की ओर हुआ विस्थापन है।[38]

मुद्रा और ऋण

अक्तूबर 2025 से संचलनगत मुद्रा में तेज़ी से विस्तार के साथ जनवरी 2026 के दौरान आरक्षित मुद्रा की संवृद्धि (सीआरआर के लिए समायोजित) में वृद्धि हुई।[39] जनवरी के मध्य में गिरावट के बावजूद, कुल जमा राशि और जनता के पास मौजूद नकदी में बढ़ोतरी के कारण बाद में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई (चार्ट IV.5)।[40]

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण और जमा वृद्धि महीने के दौरान दोहरे अंकों में बनी रही, जिसमें ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक रही (चार्ट IV.6)।[41]

2025-26 के दौरान अब तक (31 जनवरी, 2026 तक), वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह एक वर्ष पहले ₹25.5 लाख करोड़ से बढ़कर ₹34.5 लाख करोड़ हो गया (सारणी IV.2ए)। गैर-बैंकिंग स्रोतों – कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गमों और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश – में वर्ष के अब तक के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 31 जनवरी 2026 तक वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया ऋण में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें

चार्ट IV.5: आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति ($एम_3$) की वृद्धि में फिर से तेजी आई

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

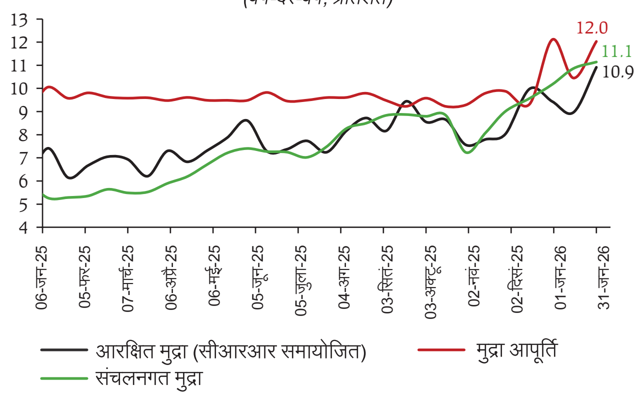

टिप्पणियां: 1. बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के ज़रिए पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का डेटा महीने के 15वें और आखिरी दिन से संबंधित है, जो 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी है।
2. मुद्रा आपूर्ति डेटा में 14 जुलाई, 2023 से एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

स्रोत: आरबीआई।

[38] दिसंबर 2025 में जारी किए गए निर्गम नवंबर 2025 में ₹0.59 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.74 लाख करोड़ हो गए। संचयी आधार पर (अप्रैल–दिसंबर), यह वर्ष 2025–26 में ₹6.83 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹7.25 लाख करोड़ से कम है।

[39] आरक्षित मुद्रा में वृद्धि (नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन के प्रथम-चरण के प्रभाव के लिए समायोजित) 31 दिसंबर, 2025 की 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 31 जनवरी, 2026 को 10.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान संचलनगत मुद्रा की वृद्धि 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़कर 11.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। 31 अक्टूबर, 2025 को संचलनगत मुद्रा में वृद्धि 7.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी।

[40] मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दर 31 दिसंबर, 2025 को 12.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से मामूली रूप से घटकर 31 जनवरी, 2026 को 12.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई।

[41] एससीबी की ऋण वृद्धि दर 31 दिसंबर 2025 को 14.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से मामूली रूप से बढ़कर 31 जनवरी, 2026 को 14.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। इसी अवधि के दौरान, एससीबी की जमा वृद्धि दर 12.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से मामूली रूप से घटकर 12.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रह गई।

चार्ट IV.6: ऋण और जमा वृद्धि मजबूत बनी रही

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

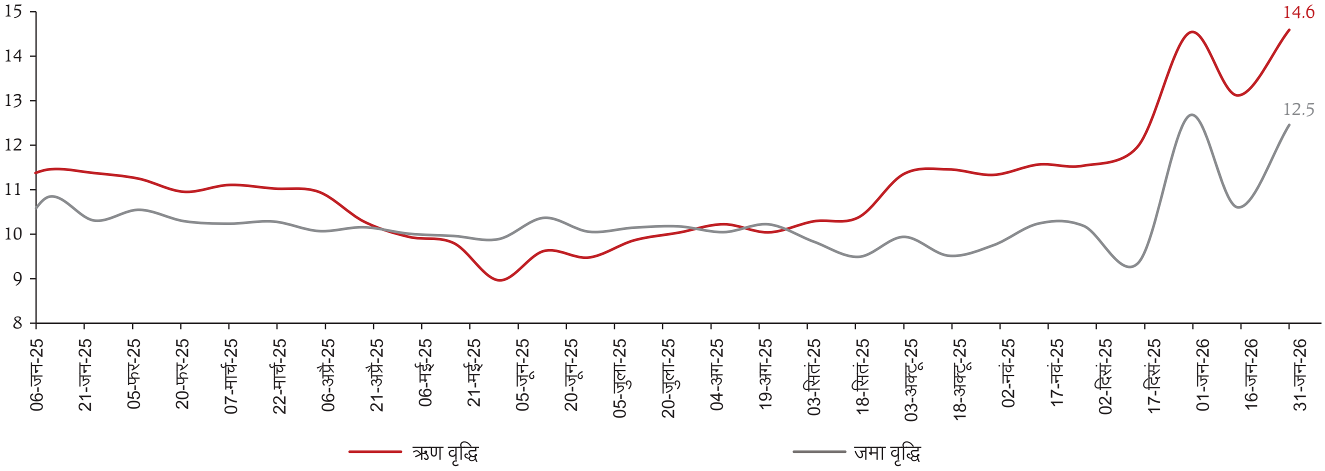

टिप्पणियां : 1. एससीबी के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव भी शामिल है।
2. बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, एससीबी के लिए डेटा महीने के 15 वें और अंतिम दिन से संबंधित है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

स्रोत: धारा 42 के अंतर्गत पाक्षिक विवरणी, आरबीआई।

गैर-बैंक स्रोतों से 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी IV.2बी)।

दिसंबर में, सभी प्रमुख क्षेत्रों में समग्र गैर-खाद्य बैंक ऋण[42] वृद्धि (वर्ष -दर -वर्ष) में मजबूती देखी गई (चार्ट IV.7)। कृषि और

सारणी IV.2ए: वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ लाख करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		31 जनवरी तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 पी
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**21.40**	**17.98**	**14.03**	**21.79**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**12.64**	**17.10**	**11.50**	**12.69**
बी1. घरेलू स्रोत	10.20	13.86	9.14	9.59
बी2. विदेशी स्रोत	2.43	3.25	2.36	3.10
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	**34.04**	**35.09**	**25.53**	**34.47**

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण आकड़ों का योग भिन्न हो सकता है।
2. विस्तृत टिप्पणियों और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (ए) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान सारणी संख्या :18(ए)।

[42] आंकड़े अनंतिम हैं। गैर-खाद्य ऋण से संबंधित आंकड़े साप्ताहिक सेक्शन-42 विवरणी पर आधारित हैं, जो सभी एससीबी को कवर करते हैं। क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण के आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जो चुनिंदा बैंकों को शामिल करते हैं जो सभी एससीबी द्वारा दी गई कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं; ये आंकड़े महीने के अंतिम रिपोर्टिंग पाक्षिक के हैं। एसआईबीसी के तहत कवर किए गए बैंक समूह हैं – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक।

सारणी IV.2बी: वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बकाया ऋण

(₹ लाख करोड़; कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं)

स्रोत	मार्च के अंत में		31 जनवरी तक	
	2024	2025	2025	2026 पी
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**164.09**	**182.07**	**178.12**	**203.86**
	(20.2)	**(11.0)**	**(11.3)**	**(14.4)**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**77.57**	**88.86**	**84.30**	**97.02**
	(4.2)	**(14.6)**	**(12.6)**	**(15.1)**
बी1. घरेलू स्रोत	56.59	66.37	62.18	72.80
	(4.9)	(17.3)	(15.5)	(17.1)
बी2. विदेशी स्रोत	20.98	22.49	22.12	24.22
	(2.4)	(7.2)	(5.2)	(9.5)
सी. कुल ऋण (ए+बी)	**241.66**	**270.94**	**262.43**	**300.88**
	(14.5)	**(12.1)**	**(11.7)**	**(14.7)**

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण आकड़ों का योग भिन्न हो सकता है।
2. गैर-बैंक स्रोतों के आंकड़ों में घरेलू स्रोतों के तहत इक्विटी और हाइब्रिड लिखत जारी किए जाने और विदेशी स्रोतों के तहत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं है।
3. बकाया डेटा के आधार पर प्रवाह सारणी IV.2ए में प्रदान किए गए प्रवाह के साथ मेल नहीं खा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित हो सकता है:
(ए) 1 जुलाई 2023 को एचडीएफ़सी बैंक के साथ एचडीएफ़सी लिमिटेड का विलय;
(बी) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में परिवर्तन; और
(सी) विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।
4. विस्तृत नोट्स और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (बी) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

कृषि और औद्योगिक ऋण वृद्धि बढ़कर दो अंकीय स्तर पर पहुंच गई। उद्योगों के भीतर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ बड़े उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। व्यापार और वाणिज्यिक रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ एनबीएफसी को बैंक ऋण देने में तीव्र वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई। आवास, स्वर्ण और वाहन ऋण खंडों की अगुवाई में व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि दर मजबूत हुई।

जमा और उधार दरें

फरवरी–दिसंबर 2025 के दौरान नीतिगत रेपो दर में संचयी 125 आधार अंकों की कटौती के जवाब में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नए और बकाया रुपए ऋणों पर भारित औसत उधार दरें क्रमशः 105 आधार अंक (बीपीएस) और 81 आधार अंक कम हो गईं। जमाराशि के मामले में, अल्प-अवधि थोक जमाओं के उच्च हिस्से के कारण नई जमाराशियों के लिए पुनर्मूल्यनिर्धारण तेजी से हुआ, जबकि मौजूदा जमा दरों में क्रमिक समायोजन देखा गया, जो मौजूदा मीयादी जमाओं की लंबी अवधि को दर्शाता है (सारणी IV.3)।

नए और बकाया रुपए ऋणों पर भारित औसत उधार दरों में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंकों के मामले में अधिक रही (चार्ट IV.8)। जमाराशियों के मामले में, नई मीयादी जमाराशियों के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संचरण निजी बैंकों की तुलना में अधिक रहा।

चार्ट IV.7: बैंक ऋण वृद्धि में तेजी दर्ज की गई

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

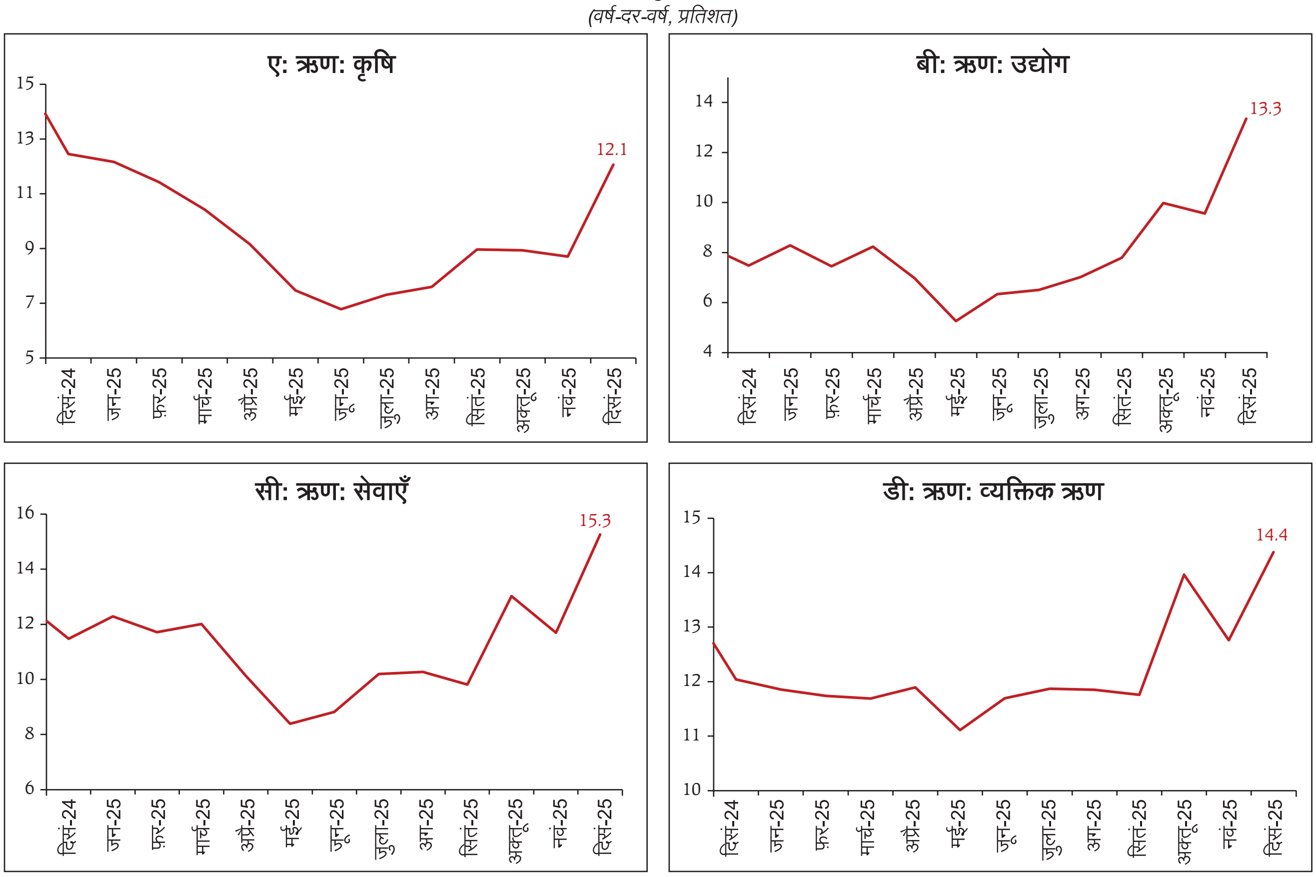

स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.3: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें				
		डब्ल्यूएडीटीडीआर- नया जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर – नया रुपया ऋण		डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण
						कुल	ब्याज दर प्रभाव#	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सख्ती की अवधि मई 2022 से जन 2025 तक	250	259	206	250	175	182	191	115
नरमी का चरण फर 2025 से दिसं 2025	-125	-95	-41	-125	-55	-105	-94	-81

#: जनवरी 2025 से भार की पर गणना की गई।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत ऋण दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर; भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर।
एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर; ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर।
टिप्पणी: ईबीएलआर पर आंकड़े 32 घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

इक्विटी बाज़ार

जनवरी 2026 में अमेरिकी आयात शुल्कों को लेकर अनिश्चितताओं और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के मद्देनजर भारतीय इक्विटी बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, जनवरी के अंत में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को लेकर व्याप्त सकारात्मक माहौल और आर्थिक सर्वेक्षण में 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के अनुमानों के प्रकाशन ने इक्विटी बाजारों को सहारा प्रदान किया (चार्ट IV.9)। फरवरी माह में, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा और 2025-26 के तीसरी तिमाही के लिए कॉरपोरेट के मजबूत कमाई के नतीजों ने इक्विटी बाजारों को ऊपर उठाने में सहायता की, हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी व्यवधानों की आशंकाओं ने लाभ को सीमित कर दिया।

वित्त के बाह्य स्रोत

अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सकल और निवल दोनों मामलों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा।[43] दिसंबर में कुल एफडीआई आवक सुदृढ़ बनी रही, जिसमें सिंगापुर, नीदरलैंड

चार्ट IV.8: बैंक समूहों के बीच संचरण (फरवरी – दिसंबर 2025)

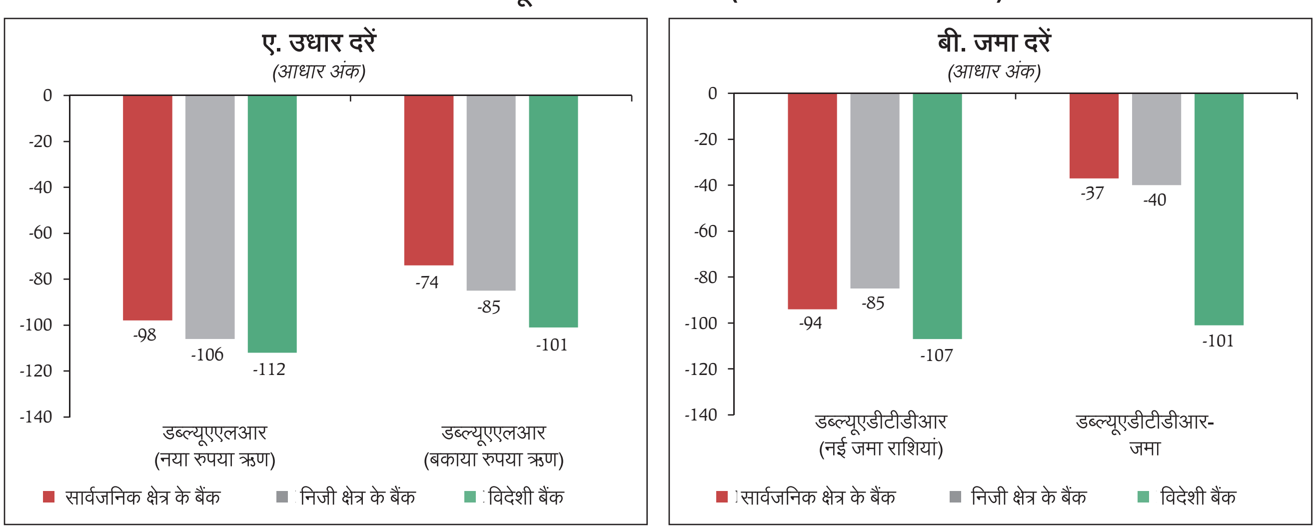

टिप्पणी: फरवरी से दिसंबर 2025 के दौरान होने वाले संचरण की गणना जनवरी 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों को दिसंबर 2025 की दरों से घटाकर की जाती है।
स्रोत: आरबीआई।

[43] अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान निवल एफ़डीआई बढ़कर 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान सकल आवक एफडीआई बढ़कर 73.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चार्ट IV.9: फरवरी में घरेलू इक्विटी बाजार में उछाल आया

(सूचकांक, बायां मान; ₹ हजार करोड़, दायां मान)

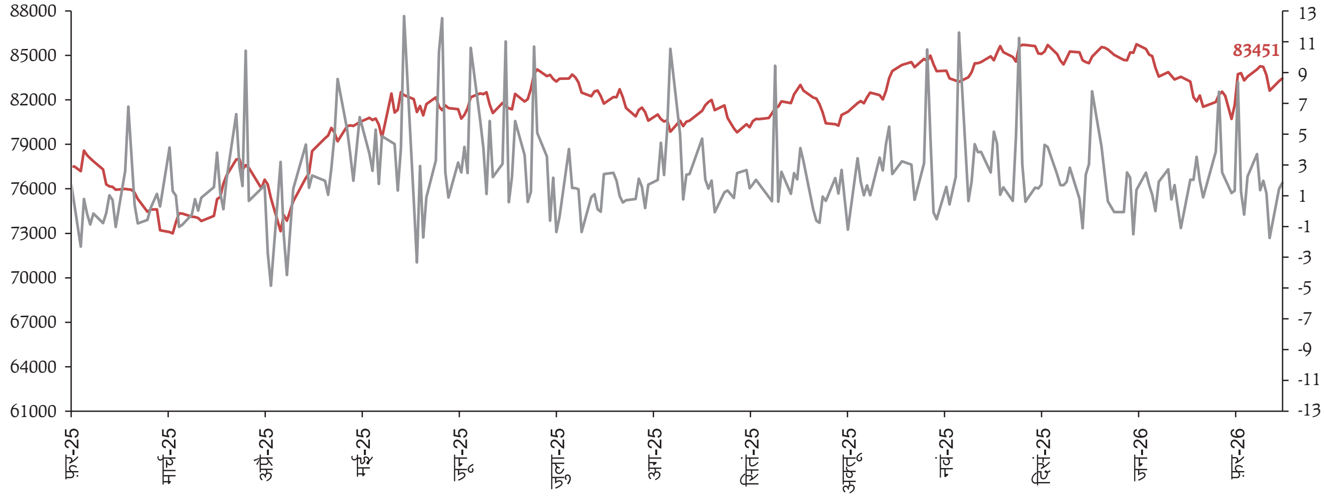

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

और मॉरीशस का कुल आवक में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा। प्रमुख प्राप्तकर्ता क्षेत्र परिवहन, विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं, और बिजली तथा अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और संचरण थे। प्रमुख प्राप्तकर्ता क्षेत्र परिवहन, विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं और बिजली और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और संचरण थे। हालांकि, दिसंबर 2025 में, प्रत्यावर्तन और जावक एफडीआई में वृद्धि के कारण लगातार चौथे महीने के लिए निवल एफडीआई नकारात्मक रहा।[44] जावक एफडीआई के लिए प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, अमेरिका, यूएई, यूके और नीदरलैंड थे और प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, और थोक/खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल शामिल थे (चार्ट IV.10)।

चार्ट IV.10: मजबूत सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

ए. सकल और निवल एफडीआई

(यूएस $ बिलियन)

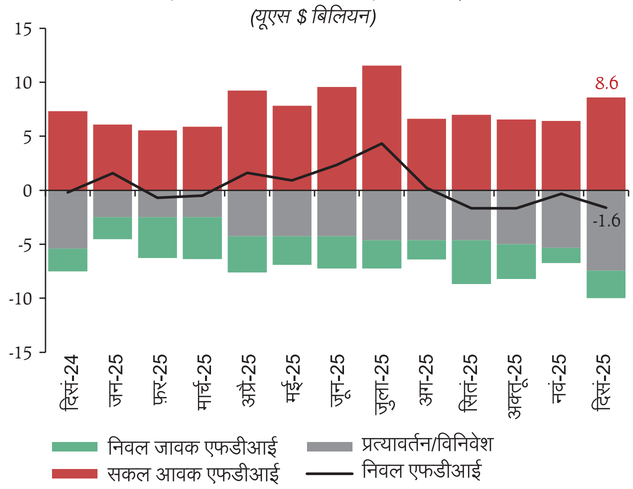

बी. दिसंबर 2025 में देश-वार जावक

(यूएस $ मिलियन)

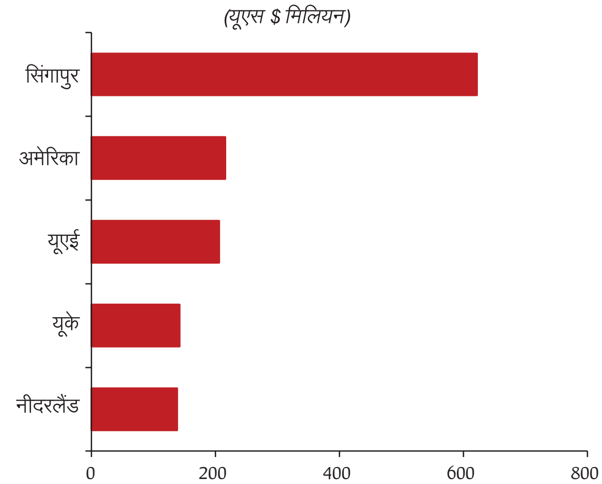

स्रोत: आरबीआई।

[44] दिसंबर 2025 में निवल जावक एफडीआई में 30.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट IV.11: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में सुधार के शुरुआती संकेत दिखे

(यूएस$ बिलियन)

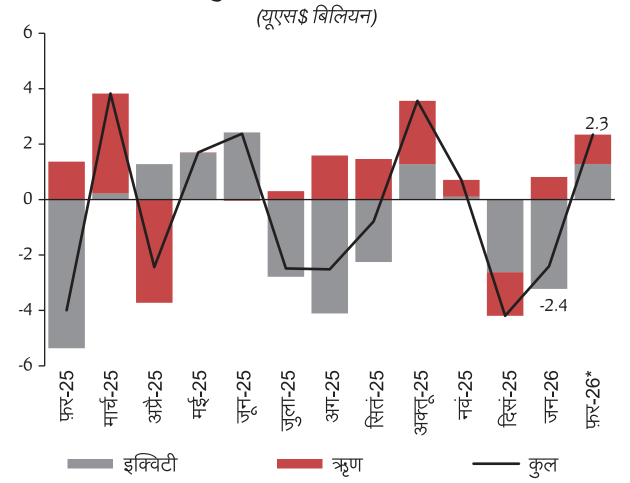

*: 16 फरवरी, 2026 तक का डेटा।
टिप्पणी: ऋण में हाइब्रिड लिखतों के अंतर्गत निवेश शामिल हैं।
स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद निवेशकों का रुख के बदलने के साथ फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने वापसी की (चार्ट IV.11)।[45]

बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) मार्ग के माध्यम से अपतटीय निधि जुटाने में चालू वित्त वर्ष में दिसंबर माह में सबसे अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए, जिसका आंशिक रूप से श्रेय दिसंबर में अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती को दिया जा सकता है। संचयी आधार पर, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के पंजीकरण और निवल अंतर्वाह दोनों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कमी आई। अन्य कारणों के अलावा, अपतटीय निधीयन में व्यापक गिरावट यह दिखाती है कि घरेलू स्तर पर ब्याज दरों में कटौती के दौर में विदेशी वित्तपोषण की मांग कम हो गई है (चार्ट IV.12)।[46]

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त बना हुआ है, जो लगभग एक साल के सामान के आयात और बकाया विदेशी कर्ज के लगभग 96 प्रतिशत हिस्से को कवर करने के लिए काफी है (चार्ट IV.13)।[47] हालांकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन 6 फरवरी, 2026 तक मूल्यांकन के प्रभाव के कारण दिसंबर के आखिर के स्तर की तुलना में सोने का हिस्सा बढ़ गया है।[48]

चार्ट IV.12: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण और प्रवाह में कमी

(यूएस$ बिलियन)

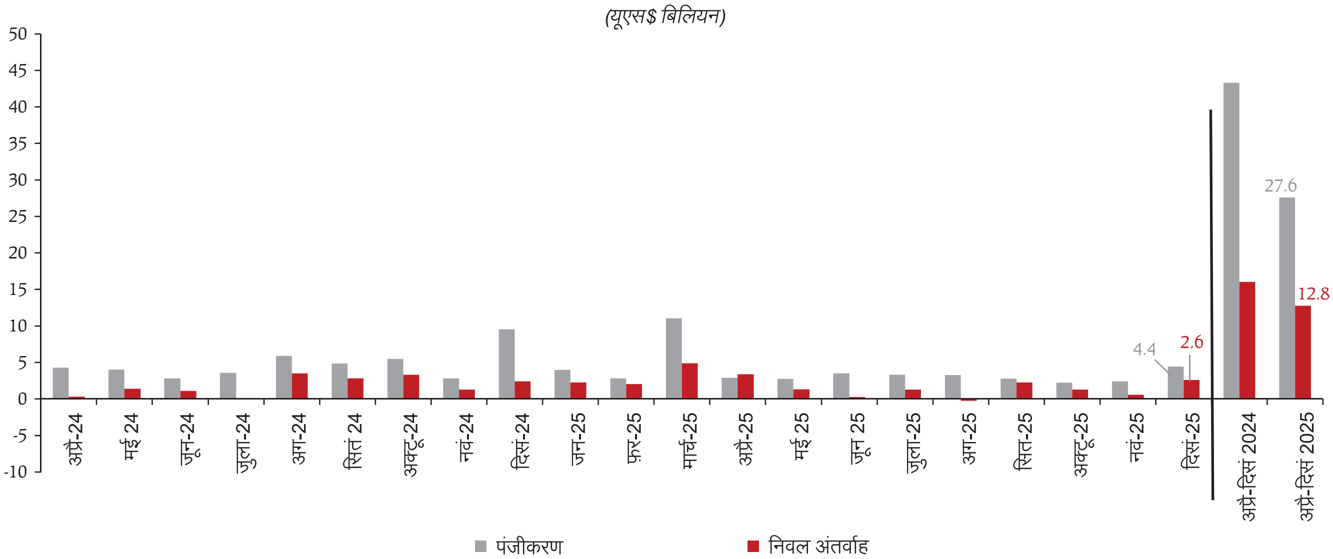

स्रोत: आरबीआई

[45] वर्ष 2025-26 में अब तक (16 फरवरी, 2026 तक), मुख्य रूप से इक्विटी खंड से निकासी के कारण, निवल एफपीआई में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया है। हालांकि, फरवरी माह में अब तक (16 तारीख तक), निवल एफपीआई में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया है।

[46] ईसीबी का पंजीकरण अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 43.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 27.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

[47] 6 फरवरी, 2026 तक, माल और सेवाओं के लिए आयात कवर लगभग नौ महीने का था।

[48] 06 फरवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी दिसंबर के अंत की 16.2 प्रतिशत की स्थिति से बढ़कर 17.2 प्रतिशत हो गई।

चार्ट IV.13: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त

(यूएस$ बिलियन, बायां मान; महीने, दायां मान)

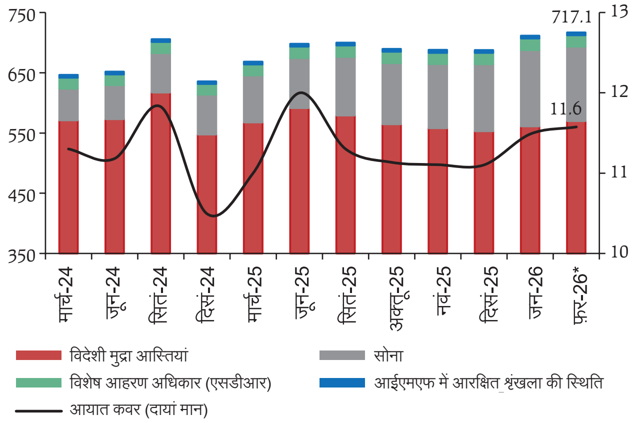

*: 6 फरवरी, 2026 तक।

टिप्पणी: आयात कवर डेटा भुगतान संतुलन सांख्यिकी के अनुसार वार्षिकीकृत पण्य आयात पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.14: निवल एफपीआई अंतर्वाह के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आईएनआर का अधिमूल्यन

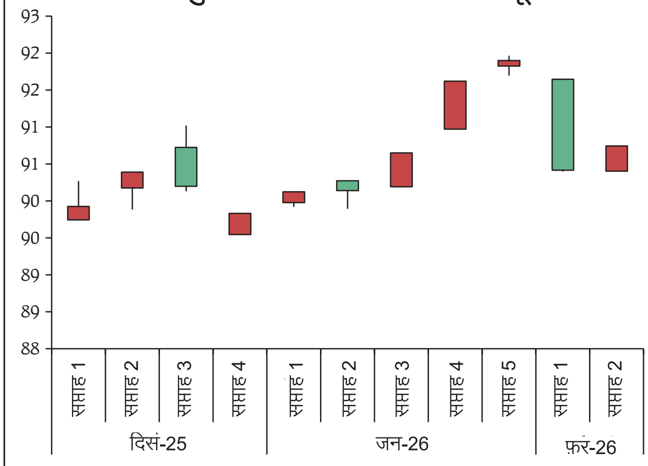

टिप्पणी: लाल कैंडल मूल्यह्रास दर्शाती हैं, अर्थात सप्ताहांत में आईएनआर खुलने की कीमत से अधिक पर बंद हुआ। हरी कैंडल अधिमूल्यन दर्शाती हैं, अर्थात सप्ताहांत में आईएनआर खुलने की कीमत से कम पर बंद हुआ।

स्रोत: आरबीआई।

विदेशी मुद्रा बाजार

जनवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपया (आईएनआर) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। फरवरी में, निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह के सकारात्मक होने के साथ, भारतीय रुपया जनवरी के निचले स्तर से सुधरा (चार्ट IV.14)। वास्तविक प्रभावी दरों के संदर्भ में, जनवरी में भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हुआ क्योंकि नाममात्र प्रभावी दरों में रुपये का मूल्यह्रास, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में भारत में उच्च कीमतों के प्रभाव से कहीं अधिक था (चार्ट IV.15)।

चार्ट IV. 15: 40 मुद्राओं की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में उतार-चढ़ाव

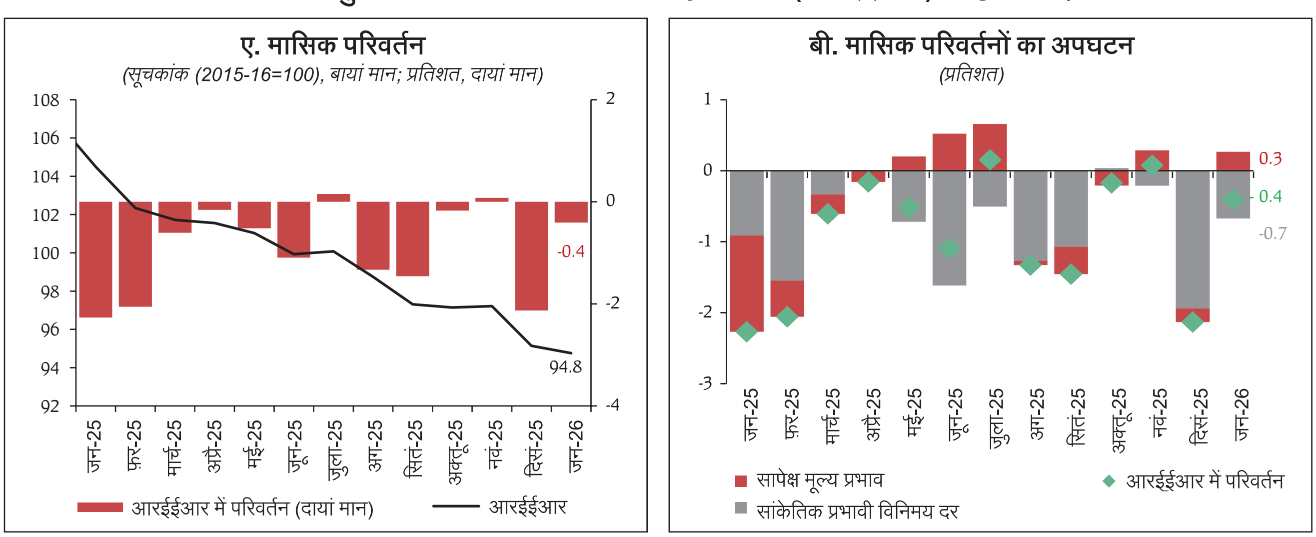

टिप्पणी: सकारात्मक परिवर्तन सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में अधिमूल्यन दर्शाता है, जबकि नकारात्मक परिवर्तन मूल्यह्रास दर्शाता है।

स्रोत: आरबीआई।

V. निष्कर्ष

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और वित्तीय बाजार की परिस्थितियां परिवर्तन की अवस्था में हैं, जो विविध संकेतों से प्रभावित होकर बाजार की गतिविधियों में कुछ मात्रा में अस्थिरता उत्पन्न कर रही हैं। एक ओर भू-राजनीतिक तनाव, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में सार्वजनिक ऋण के धारणीयता को लेकर चिंताएं, एआई कंपनियों के अत्यधिक ऊँचे मूल्यांकन और सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग पर एआई के विघटनकारी प्रभाव परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कॉरपोरेट कमाई सहित सुदृढ़ समष्टि आर्थिक डेटा के जारी होने ने सकारात्मक रुख को बढ़ावा दिया है।

जनवरी के अंत में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार वार्ताओं के पूर्ण होने और इसके पश्चात भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम व्यापार करार की आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, जिससे बाजार पहुंच में सुधार होगा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और भारतीय फर्मों का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में और गहराई से एकीकरण होगा। तत्काल प्रभाव में, इसने निवेशकों के रुख में परिवर्तन लाया है। फरवरी माह में इक्विटी और ऋण खंडों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने वापसी की है।

राजकोषीय मोर्चे पर, राजकोषीय सुदृढीकरण और ऋण धारणीयता के लिए निरंतर प्रतिबद्धता विवेकपूर्ण समष्टि आर्थिक प्रबंधन का संकेत देती है। राजकोषीय घाटे में धीरे-धीरे कमी और साथ ही पूंजीगत व्यय पर लगातार ज़ोर देने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलने और उत्पादक क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। राज्यों को पूंजी निवेश के लिए दी गई सहायता से उप-राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि और अवसंरचना विकास को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था के लिए निकट अवधि का आर्थिक दृष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है और उपभोग, निवेश और उत्पादकता-बढ़ाने वाले सुधारों द्वारा संचालित अपनी उच्च विकास गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।[49] मुद्रास्फीति लक्ष्य[50] के निकट और सौम्य बने रहने की उम्मीद है, जिससे अल्पावधि में विकास और मुद्रास्फीति का संतुलन सकारात्मक रहने की संभावना है।

---

[49] मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 6 फरवरी, 2026 के संकल्प में 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए वृद्धि के अनुमानों में प्रत्येक में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इन्हें क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत कर दिया गया है।

[50] मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 6 फरवरी, 2026 के प्रस्ताव में वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 2.1 प्रतिशत लगाया गया है, जिसमें चौथी तिमाही के लिए यह 3.2 प्रतिशत है। 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान अब क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत लगाया गया है।

अनुलग्नक

बॉक्स ए: संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का मूल्य आधार वर्ष संशोधित कर 2012=100 से बदलकर 2024=100 कर दिया गया है। नए आधार वर्ष के लिए भार संदर्भ अवधि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 पर आधारित है, जो समकालीन उपभोग स्वरूप और संरचनात्मक आर्थिक बदलावों को दर्शाती है।

संशोधित श्रृंखला में सर्वेक्षित बाजारों और मदों का कवरेज बढ़ाया गया है (299 से बढ़ाकर 358 कर दिया गया है), साथ ही ऑनलाइन बाजार मूल्य डेटा का भी एकीकरण किया गया है। संशोधित बास्केट से यह पता चलता है कि जिन मदों में ऐतिहासिक रूप से मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव रहा है, उनका भार तुलनात्मक रूप से कम है।

प्रणाली संबंधी संवर्धन में नियोक्ता-प्रदत्त आवास और निःशुल्क सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों को बाहर रखना, ग्रामीण आवास सूचकांकों का परिचय, कुछ अनुपलब्ध डेटा (जिसमें मौसमी मदें भी शामिल हैं) के लिए अनुमानित मान, और गुणवत्ता तथा विनिर्देशों में होने वाले बदलावों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए प्राथमिक स्तर पर श्रृंखला-आधारित सूत्रों को अपनाना शामिल है।

चूंकि वर्गीकरण में परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पुरानी और नई श्रृंखला के बीच भारों की विभिन्न श्रेणियों में सख्ती से तुलना नहीं की जा सकती। नई संरचना के तहत, 'खाद्य और पेय पदार्थ' प्रभाग का भार वर्ष 2012 की श्रृंखला में निहित 45.9 प्रतिशत से घटकर 36.8 प्रतिशत रह गया है, जिसमें से 3.3 प्रतिशत की कमी का कारण तैयार खाद्य वस्तुओं और नाश्ते को 'रेस्तरां और आवास सेवाएं' नामक एक नए प्रभाग में पुनर्वर्गीकृत किया जाना है। खाद्य समूह के भीतर, अनाज का भार 9.7 प्रतिशत से घटकर 5.9 प्रतिशत, दलहन का भार 2.4 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत, सब्जियों का भार 6.0 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत, तथा तेल और वसा का भार 3.6 प्रतिशत से घटकर 2.7 प्रतिशत रह गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के कोर (जिसमें खाद्य और ईंधन को छोड़ दिया गया है) का भार 47.3 प्रतिशत से बढ़कर 57.9 प्रतिशत हो गया है (जिसमें रेस्तरां और आवास सेवाएं शामिल हैं) [चार्ट ए1]।

चार्ट ए1: संशोधित सीपीआई भार संरचना

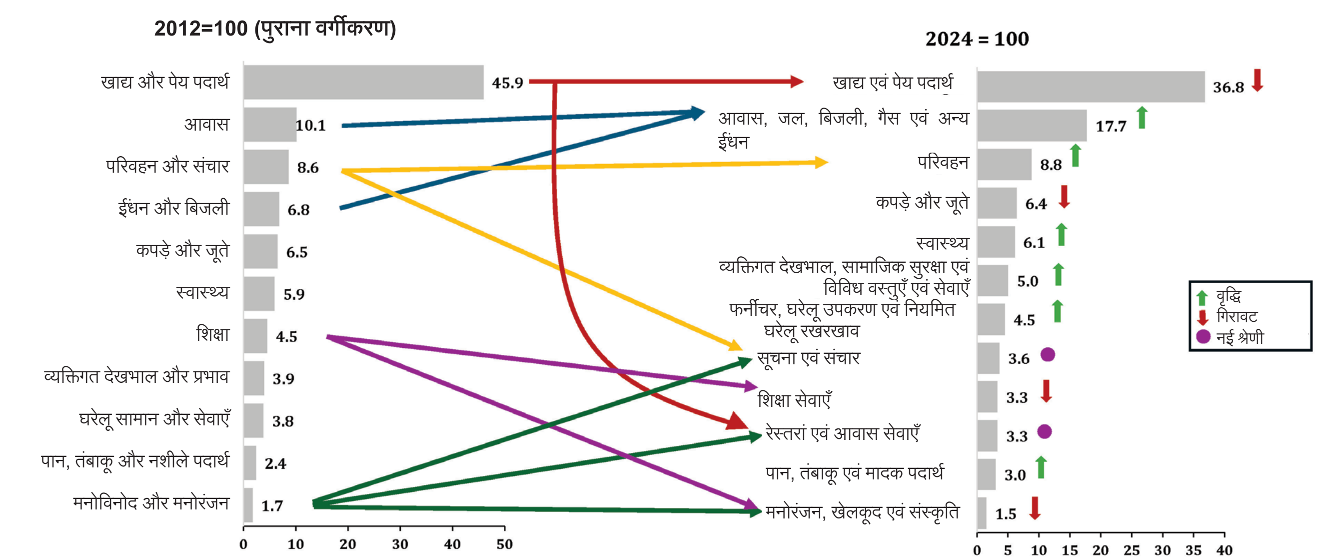

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

स्रोत: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्यापक अद्यतन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (जनवरी 2026)।